



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1939 (श0)

(सं0 पटना 926) पटना, मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2017

सं0 3018/एम0—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम 67, 1957) की धारा 15 के सपठित धारा 23 ग एव धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।** — (1) यह नियमावली बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।  
(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।  
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ।** (1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—
  - (i) “अधिनियम” से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम 67, 1957);
  - (ii) “समाहर्ता” से अभिप्रेत है, जिला का समाहर्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी अथवा समाहर्ता—सह—जिला दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो;
  - (iii) “सक्षम पदाधिकारी” से अभिप्रेत है:—
    - (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केन्द्रीय अधिनियम xvi, 1927) के अधीन सुरक्षित और संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित भूमि में उत्खनन अनुज्ञापत्र (अनुज्ञापत्र) की दशा में जहाँ वास्तविक खनन कार्य केवल सतह से अथवा पाँच फीट से अनधिक गहराई से कुछ हटाना मात्र हो तथा केवल 10,000 घन फीट की सीमा तक हो, संबंधित सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र का प्रमंडलीय वन पदाधिकारी;

- (ख) सभी भूमि तथा भूमिगत मिट्टी, जिसमें खान और खनिज का कोई अधिकार, चाहे खोजा गया हो तथा चाहे उसपर कार्य किया जा रहा हो या नहीं, सम्मिलित है, की बाबत अन्य सभी मामलों में जिला का खनन पदाधिकारी;
- (iv) “निगम” से अभिप्रेत है बिहार राज्य खनन निगम;
- (v) “विभाग” से अभिप्रेत है खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार;
- (vi) “प्रमंडलीय आयुक्त” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्रमंडल का आयुक्त;
- (vii) “खान निदेशक” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त खान निदेशक;
- (viii) “निर्यात” से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क की सीमांत चौकी के पार बिहार राज्य से बाहर ले जाना;
- (ix) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार;
- (x) “आयात” से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा शुल्क की सीमांत चौकी के पार से बिहार राज्य में लाना;
- (xi) “स्थानीय प्राधिकार” से अभिप्रेत है नगरपालिक समिति, जिला परिषद अथवा स्थानीय निधि के नियंत्रण अथवा प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार अथवा सरकार द्वारा न्यस्त अन्य प्राधिकार;
- (xii) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से अभिप्रेत है ऐसा पदाधिकारी जो अधिनियम और इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा, फुटकर अनुज्ञप्ति, संचालन अनुज्ञप्ति अथवा कोई अन्य अनुज्ञप्ति स्वीकृत, निलंबित और रद्द करने के लिए प्राधिकृत हो;
- (xiii) “खान आयुक्त” से अभिप्रेत है आयुक्त, खान एवं भूतत्व, बिहार अथवा इस नियमावली के अधीन आयुक्त के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी;
- (xiv) “लघु खनिज” से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (ड) में यथा परिभाषित लघु खनिज और इसमें सम्मिलित हैं—
- (क) बालू, मोरम, चिप्स, पत्थर, बोल्टर, ईट, ईट-मिट्टी, साधारण मिट्टी जो भूमि को भरने में प्रयुक्त होते हैं, नदी तल में पाये जाने वाले बजरी/बोल्टर, सजावटी पत्थर, चाइना क्ले, क्वार्टज, मार्बल, सैंड स्टोन, सिलिका सैंड, आदि जैसे लघु खनिज;
- (ख) ऐसे लघु खनिज जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस.ओ. 423, दिनांक-10.02.2015 द्वारा अधिसूचित है;
- (xv) “खनिज निपटान अनुज्ञापत्र” से अभिप्रेत है निम्नलिखित के निपटान हेतु दिया गया अनुज्ञापत्र—
- (क) किसी नाला अथवा नहर अथवा नदी के अनुरक्षण/अपवहन की प्रक्रिया के दौरान उत्खनित अथवा उत्पन्न लघु खनिज/गाद/प्लाई ऐश/झामा/ राबिस अथवा कोई उपोत्पाद;
- (ख) किसी भवन अथवा संरचना के निर्माण अथवा मरम्मती अथवा विध्वंस की प्रक्रिया के दौरान उत्खनित अथवा उत्पन्न उपोत्पाद लघु खनिज/गाद/प्लाई ऐश/झामा/राबिस अथवा कोई उपोत्पाद;
- (ग) बाढ़ अथवा किसी उत्पादन क्रियाकलाप के कारण उत्खनित अथवा उत्पन्न अथवा जमा लघु खनिज/गाद/प्लाई ऐश/झामा/राबिस अथवा कोई उपोत्पाद;
- टिप्पणी** — खनिज निपटान अनुज्ञापत्र रखनेवाले किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान उक्त खनिजों के परिवहन के लिए नियम 2(1)(xx) में यथापरिभाषित संचलन अनुज्ञापत्र अपेक्षित नहीं है।
- (xvi) “खनन पट्टा” से अभिप्रेत है लघु खनिजों की बाबत खनन पट्टा या बन्दोबस्ती अथवा अनुज्ञापत्र तथा इसके अन्तर्गत इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार लघु खनिज (खनिजों) के खनन की अनुमति देनेवाले उत्खनन अनुज्ञापत्र और कोई अन्य खनिज समनुदान हैं;
- (xvii) “खनन योजना” से अभिप्रेत है लघु खनिजों की ओर से मान्यताप्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा तैयार की गई योजना और इसमें उत्तरोत्तर और अंतिम खान बंदी योजना है;
- (xviii) “खनन पदाधिकारी” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 5 के अधीन यथाउल्लिखित पदाधिकारी;
- (xix) “खनन राजस्व” से अभिप्रेत है इस नियमावली से संबंधित अथवा किसी अन्य कानून के अधीन अधिरोपित अथवा आदेशित किसी स्वामिस्व, फीस, कर, भुगतान (दंड न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना से भिन्न) अथवा जब्ती से प्राप्त अथवा प्राप्त होने योग्य राजस्व;
- (xx) “संचलन अनुज्ञापत्र” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी लघु खनिज के संचलन के लिए स्वीकृत प्राधिकरण;

- (xxi) “स्थान” के अन्तर्गत भवन, मकान, दुकान, नाव (बोट), बूथ, जलयान, रैफ्ट, यान, वाहन अथवा टेंट का घेरा है।
- (xxii) “सार्वजनिक स्थान” से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ लोगों की पहुँच हो चाहे अधिकार स्वरूप अथवा नहीं और इसमें लोगों द्वारा जाए जाने वाले सभी स्थान हैं तथा कोई खुली जगह भी शामिल है;
- (xxiii) “थाना” से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 2 के खंड (s) के अधीन यथा परिभाषित थाना;
- (xxiv) “विहित” से अभिप्रेत है इस नियमावली अथवा मार्गदर्शन द्वारा विहित;
- (xxv) “लोक माँग” से अभिप्रेत है बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (अधिनियम 4, 1914) के अधीन यथापरिभाषित लोक माँग;
- (xxvi) “मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो नियम 20 के अधीन विभाग द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया हों;
- (xxvii) “फुटकर अनुज्ञप्ति” से अभिप्रेत है लघु खनिज के फुटकर क्रियाकलाप, जिसमें ईट-उत्पादन क्रियाकलाप शामिल है, को जारी रखने के लिए इस नियमावली के अधीन स्वीकृत फुटकर अनुज्ञप्ति;
- (xxviii) “बालूघाट” से अभिप्रेत है बालू रखनेवाला क्षेत्र जहाँ से बालू निकाले जा सकते हैं तथा वाहक द्वारा ढोये जा सकते हैं;
- (xxix) “बन्दोबस्तधारी” से अभिप्रेत है बन्दोबस्ती अथवा पट्टा धारण करने वाले क्षेत्र से बालू और अन्य लघु खनिजों के उत्खनन/उठाने के लिए वैध बन्दोबस्ती/पट्टा धारण करने वाला कोई व्यक्ति (इस नियमावली में यथा परिभाषित) तथा इसके अन्तर्गत इसके बहुवचन भी होंगे।
- (xxx) “बन्दोबस्ती” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, इसमें विनिर्दिष्ट बालू और अन्य लघु खनिज (खनिजों) के उत्खनन, जीत, कार्य, ढोने के लिए सरकार की ओर से दिया जानेवाला खनन अधिकार;
- (xxxi) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार;
- (xxxii) “बालू नीति, 2013” से अभिप्रेत है राज्य सरकार की अधिसूचना सं० 2214, दिनांक-27.08.2013 द्वारा यथा अधिसूचित बालू नीति;
- (xxxiii) “अस्थायी संरचना” से अभिप्रेत है कोई ऐसी संरचना जिसमें नींव खड़ी करना अपेक्षित न हो और जो आसानी से ध्वस्त की जा सकती हो, जिसकी रूपरेखा को बहुत आसानी से परिवर्तित की जा सकती हो;
- (xxxiv) “पारगमन” से अभिप्रेत है बिहार राज्य से होकर एक राज्य से दूसरे राज्य में आना-जाना;
- (xxxv) “परिवहन” से अभिप्रेत है बिहार राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना;
- (xxxvi) “भांडागार” से अभिप्रेत है वह स्थान जहाँ लघु खनिज के भंडारण की अनुमति हो;
- (xxxvii) “कार्य विभाग” से अभिप्रेत है राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभाग जो सड़क, रेल, भवन, बांध जलापूर्ति इत्यादि जैसी लोक परियोजनाओं में लगे हो।
- (2) इस नियमावली, प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति समानुद्देशित किये गये हो।

## अध्याय II

### स्थापना और नियंत्रण

3. **खान आयुक्त की नियुक्ति।** — राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य स्तर पर इस नियमावली के प्रशासन के लिए जवाबदेह होंगे।
4. **खान निदेशक की नियुक्ति।** — राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खान निदेशक की नियुक्ति कर सकेगी जो जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में इस नियमावली के प्रशासन के लिए जवाबदेह होंगे।
5. **खनन पदाधिकारी।** — (1) खान आयुक्त, खान निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला खनन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी और खनन निरीक्षक इस नियमावली के प्रयोजनार्थ खनन पदाधिकारी होंगे।  
(2) समाहर्ता अथवा उनके जिले के भीतर उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ खनन पदाधिकारी की शक्तियों के प्रयोग के लिए सक्षम होंगे।
6. **शक्तियों का प्रत्यायोजन और वापस लेना।** — (1) राज्य सरकार उन निर्वधनों और शर्तों के अधीन, खान आयुक्त अथवा समाहर्ता को, शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी जो प्रत्यायोजन आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय।  
(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी पदाधिकारी अथवा व्यक्ति से इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई अथवा सभी शक्तियाँ वापस ले सकेगी।

- 7. समाहर्ता की भूमिका।** – (1) जिले का समाहर्ता इस अधिनियम अथवा इस नियमावली के उपबंधों के सम्पूर्ण कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह होगा।  
 (2) समाहर्ता इस नियमावली के अधीन खनन पदाधिकारी की शक्तियों के प्रयोग के लिए भी सक्षम होगा।  
 (3) समाहर्ता का जिले के सभी खनन पदाधिकारियों का सीधा नियंत्रण एवं अधीक्षण होगा।  
 (4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पदाधिकारी को, जो खान विभाग के निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो अथवा राजस्व विभाग के उप समाहर्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, समाहर्ता की शक्तियों, उन पदनामों, शक्तियों और कर्तव्यों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो वह उचित समझे।
- 8. पुलिस अधीक्षक की भूमिका।** – (1) पुलिस अधीक्षक अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में समाहर्ता की मदद करेगा;  
 (2) समाहर्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण और अधीक्षण में कार्य करेगा;  
 (3) समाहर्ता अथवा खान आयुक्त अथवा खान निदेशक के ऐसे वैध निदेशों को सुनिश्चित और कार्यान्वित करेगा जो अधिनियम और इस नियमावली के अधीन निर्गत किया जाये;  
 (4) प्रतिवेदनों को ऐसी रीति से समर्पित करेगा जो समाहर्ता अथवा खान आयुक्त अथवा निदेशक खान चाहे।
- 9. खान आयुक्त की शक्तियाँ और कृत्य।** – खान आयुक्त –  
 (i) राज्य में सभी खान पदाधिकारियों पर सम्पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण का प्रयोग करेगा;  
 (ii) किसी बन्दोबस्तधारी या अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी से नोटिस द्वारा ऐसे दस्तावेज, लेखा अथवा अन्य साक्ष्य अपने समक्ष प्रस्तुत करने अथवा करवाने की अपेक्षा कर सकेगा जो उचित समझा जाय;  
 (iii) अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन किसी अधीनस्थ प्राधिकारी, पदाधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा संचालित कार्यवाही के अभिलेख को स्वप्रेरणा से मँगा सकेगा और जाँच कर सकेगा और यदि उसके विचार में उसमें पारित आदेश गलत हो अथवा राजस्व, खनन नियमावली और पर्यावरणीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो तो बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारियों अथवा सम्बद्ध व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे;  
 (iv) बंदोबस्तधारियों अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारकों आदि की क्रियाकलापों का अनुश्रवण करेगा और यदि उसका प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाये कि कोई बंदोबस्तधारी अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारी आदि पट्टा/फटकल अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन किया है अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा निर्गत विधि पूर्ण निदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो वह समाहर्ता को उस पट्टे अथवा अनुज्ञप्ति को रद्द/निलंबित करने हेतु कार्यवाही आरंभ करने के लिए निदेश देगा:  
 परन्तु समाहर्ता उक्त उल्लंघन के विरुद्ध विस्तृत जांच-पड़ताल करेगा और तब नियम 56 के अनुसार उक्त बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस निर्गत करने हेतु अग्रसर होगा।
- 10. खान निदेशक की शक्तियाँ और कृत्य।** – (1) वह खान निदेशालय का प्रधान होगा और विभाग के सभी खनन पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।  
 (2) वह राज्य में सभी खनन कार्यों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी जवाबदेह होगा कि राज्य का हित संरक्षित रहे और सभी बन्दोबस्तधारी, निगम, अन्य अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार कार्य करें।  
 (3) वह स्वामिस्व (सॉयल्टी) एवं अन्य देय राजस्व के संग्रहण के लिए जवाबदेह होगा।  
 (4) उसके अधीन सुरक्षा निदेशालय होगा जो सिविल/पुलिस कार्मिकों अथवा सेवानिवृत्त रक्षा/अर्द्ध सैनिक/पुलिस कार्मिकों में से या तो प्रतिनियुक्ति या भरती से पर्याप्त कार्मिकों को नियुक्त करेगा।  
 (5) सुरक्षा निदेशालय, निदेशक के नियंत्रण और अधीक्षण में कार्य करेगा तथा जो इस नियमावली के अध्याय XI के अधीन अपराधों के अनुसंधान सहित ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें।  
 (6) सुरक्षा निदेशालय की संरचना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
- 11. जिला स्तर पर खनन कार्यालय।** – (1) राज्य के सभी जिलों में एक खनन कार्यालय होगा जिसका प्रधान समुचित खनन पदाधिकारी होगा और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।  
 (2) जिला खनन कार्यालय के प्रधान सभी खनन पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- 12. विशेष शक्ति सम्पन्न व्यक्ति।** – राज्य सरकार अधिनियम और इस नियमावली को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को, जो खनन पदाधिकारी नहीं हो, इस नियमावली के अधीन किसी खनन पदाधिकारी के किसी कृत्य को पालन करने के लिए शक्तियों से सशक्त कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति इन कृत्यों का प्रयोग करते हुए खनन पदाधिकारी समझा जाएगा।

### अध्याय III

#### लघु खनिजों के लिए खनन पट्टा की सामान्य शर्तें

13. **लघु खनिजों के खनन पर निर्बंधन।** — कोई व्यक्ति यथास्थिति वैध खनन पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति अथवा संचलन अनुज्ञापत्र के बिना किसी लघु खनिज का उत्खनन, उत्पादन, निर्माण, वितरण, परिवहन, संग्रहण, भंडारण, कब्जा, क्रय, विक्रय नहीं करेगा:  
परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी को ऐसे क्रियाकलापों को करने की अनुमति दे सकेगी जिसे वह विनिर्दिष्ट करे।
14. **पट्टा आधार पर खनन का होना।** — सभी खनिजों का खनन, पट्टा के आधार पर किया जाएगा। कोई व्यक्ति अथवा फर्म जो खनन अथवा उत्खनन अथवा लघु खनिजों का उत्पादन करता है बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी कहलाएगा। कोई बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी न तो भूमि और न खनिजों के स्वामी होने का इसलिए दावा कर सकेगा कि वह उत्खनन कार्य करेगा।
15. **खनन क्षेत्र अथवा खनन भूखंड।** — कोई खनन क्षेत्र सामान्य रूप से पाँच हेक्टेयर से कम का नहीं होगा। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र 'खनन भूखंड' कहलाएगा:  
परन्तु राज्य सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. एस.ओ. 141 डू दिनांक 15.01.2016 और समय-समय पर यथा निर्गत मार्गदर्शन के निर्बंधनों के अनुसार खनन भूखंड को 5 हेक्टेयर से कम अथवा 5 हेक्टेयर से अधिक रखने पर निर्णय कर सकेगी।
16. **खनन गुच्छ (कलस्टर)।** — राज्य सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के निर्बंधनों तथा समय-समय पर यथा निर्गत उनके मार्गदर्शन के अनुसार खनन भूखंडों के समूह को गुच्छों में अभिहित कर सकेगी।
17. **खनन गहराई।** — बालू घाटों की दशा में खनन गहराई 3 मीटर अथवा जल स्तर, जो कम हो, होगी।
18. **खनन पट्टा की अवधि।** — सामान्यतः लघु खनिजों के लिए पट्टा की अवधि 5 वर्षों की होगी:  
परन्तु राज्य सरकार किसी विशिष्ट लघु खनिज के लिए विशिष्ट पट्टों को 3 वर्षों की अवधि अथवा उससे कम अवधि, जो हरेक मामले पर निर्भर करेगी, बंदोबस्त करने हेतु विनिश्चय कर सकेगी।
19. **खनन योजना।** — खनन योजना हरेक खनन भूखंड अथवा खनन गुच्छ के लिए तैयार की जाएगी। हरेक बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व खनन योजना, समाहर्ता को समर्पित करनी होगी। ऐसी खनन योजना किसी मान्यताप्राप्त अर्हित व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी। खनन योजना के अनुमोदन के लिए विभाग विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
20. **मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति।** — (1) कोई मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति वह व्यक्ति हो जो अभियंत्रण में स्नातक विशेषकर खनन औद्योगिकी में, भूतत्व या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक के साथ खनन/निर्माण/वास्तुविद प्रक्षेत्र में कम-से-कम 3 वर्षों का कार्यानुभव हो।  
(2) विभाग मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा जो बन्दोबस्तधारियों की ओर से खनन योजना बनाएगा।  
(3) विभाग मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति के रूप में पैनलित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड को शिथिल कर सकेगा।
21. **पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र।** — हरेक बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. 1533क, दिनांक 14.09.2006 के निर्बंधनों के अनुसार वैध पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना है :  
परन्तु यह और कि बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला समाहर्ता द्वारा समय-समय पर निर्गत पर्यावरणीय संरक्षण और पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र से संबंधित अन्य अनुदेशों का अनुपालन करेगा।
22. **खनिज विकास निधि।** — सभी बन्दोबस्तधारी, अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति अथवा अस्तित्व जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित हो, खनिज विकास निधि में प्रति वर्ष पट्टा राशि के दो प्रतिशत जमा करेगा जिसे इस नियमावली के अध्याय XVI में यथाउपदर्शित खनिज विकास फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाएगा:  
परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अंशदान के प्रतिशत को घटा या बढ़ा सकेगी।
23. **बालू घाटों पर शारीरिक श्रमिक।** — (1) बालू घाटों की दशा में पोकलेन, लोडर्स, उत्खनन आदि जैसी किसी मशीन अथवा उपस्कर को सामान्यतया उत्खनन के प्रयोजनों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। बालू घाटों से बालू का उत्खनन अधिमानतः शारीरिक श्रमिक का उपयोग कर किया जाना चाहिए:  
परन्तु विभाग अथवा समाहर्ता किसी आपात स्थिति में अथवा श्रमिक की कमी होने पर ऊपर उल्लिखित मशीनों के प्रयोग की अनुमति दे सकेगा।  
(2) पर्यावरण की दृष्टि से बालू घाटों तथा उनकी पारिस्थिति को संरक्षित करने के प्रयोजनार्थ विभाग और अधिक मार्गदर्शन निर्धारित कर सकेगा।

- 24. बालू घाटों पर खनन के लिए सामान्य प्रतिबंधित क्षेत्र।** — (1) रेल पुल अथवा सड़क पुल से 300 मीटर तक खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।  
 (2) किसी श्मशान भूमि/धार्मिक स्थान से 50 मीटर तक खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।  
 (3) नदी के दोनों तरफ जल स्रोत से 5 मीटर अन्दर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।  
 (4) उपर्युक्त के अतिरिक्त समाहर्ता खनन योजना में ही हरेक पट्टा के लिए अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- 25. खनन पट्टा की संख्या और क्षेत्र पर प्रतिबंध।** — किसी व्यक्ति अथवा फर्म को 100 हेक्टेयर से अधिक के लिए खनन अनुज्ञप्ति रखने की अनुमति नहीं होगी।  
 परन्तु विभाग किसी व्यक्ति अथवा फर्म को ऐसे खनन क्षेत्र में 100 हेक्टेयर से अधिक की अनुमति दे सकेगा यदि यह पाया जाता है कि उक्त खनन क्षेत्र हेतु भावी बोली लगाने वालों में पर्याप्त इच्छा नहीं दिख रही है।
- 26. वन क्षेत्रों में खनन।** — (1) किसी वन क्षेत्र में पड़े लघु खनिजों की समाहर्ता द्वारा उन शर्तों के साथ बोली लगाई जा सकेगी कि भावी बन्दोबस्तधारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन विभाग से सम्यक् अनुमति लायेगा।  
 (2) औपचारिक पट्टा विलेख, वन विभाग से अपेक्षित स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही, निष्पादित किया जाएगा।
- 27. रैयती भूमि पर खनन।** — (1) जहाँ कहीं किसी रैयती भूमि पर लघु खनिज का पता चलता है अथवा उपलब्ध होता है, वहाँ समाहर्ता इस नियमावली में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उक्त लघु खनिज की नीलामी के लिए सक्षम होगा।  
 (2) समाहर्ता रैयत के साथ ऐसा करार कर सकेगा और ऐसे प्रतिकर का भुगतान कर सकेगा जैसा परस्पर करार हुआ हो।  
 (3) ऐसा रैयत खजिन के उत्खनन के लिए स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं करेगा तथा उसे सार्वजनिक नीलामी में भाग लेना होगा।
- 28. साधारण मिट्टी के उत्खनन के लिए विशेष अनुज्ञप्ति।** — (1) जिला में साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन के लिए विशेष अनुज्ञप्तियाँ दी जायेंगी।  
 (2) साधारण मिट्टी की ऐसी अनुज्ञप्ति तथा खनन/उत्खनन तथा व्यापार के लिए विभाग विस्तृत मार्गदर्शन निर्धारित करेगा।
- 29. ईट भट्टा मालिक के लिए विशेष अनुज्ञप्ति।** — (1) हरेक ईट भट्टा मालिक को ईट भट्टा संचालित करने के लिए तथा ईट मिट्टी से ईट बनाने के लिए फुटकर अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अपेक्षित होगा।  
 (2) ईट और ईट मिट्टी की ऐसी फुटकर अनुज्ञप्ति और खनन/उत्खनन तथा व्यापार के लिए विभाग विस्तृत मार्गदर्शन निर्धारित करेगा।
- 30. खनिज निपटान के लिए अनुज्ञापत्र।** — (1) इस नियमावली के नियम 2 के उप नियम (XV) के अनुसार उत्खनन के इच्छुक हरेक व्यक्ति को समाहर्ता से खनिज निपटान अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा।  
 (2) ऐसे खनिज निपटान अनुज्ञापत्र के लिए विभाग विस्तृत मार्गदर्शन अधिकथित करेगा।
- 31. बंदोबस्तधारी और अनुज्ञप्तिधारियों के बीच संबंध।** — कोई व्यक्ति एक ही समय कोई बंदोबस्तधारी अथवा कोई अनुज्ञप्तिधारी नहीं हो सकता। इस नियम के अंतर्गत कोई भी बंदोबस्तधारी को अन्य कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी।
- 32. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी।** — समाहर्ता सभी खनन पट्टे तथा किसी अन्य अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी होगा। तथापि वह संचलन अनुज्ञप्ति, ई-चालान तथा ऐसे ही अन्य कृत्यों को जिले के किसी खनन पदाधिकारी को प्रत्योजित कर सकेगा।
- 33. अन्य शर्तें।** — (1) विभाग किसी बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को पर्यावरण संबंधी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा एवं साथ ही यह निदेशित कर सकेगा कि वह खनन स्थल अथवा अपने परिसर में धर्मकांटा, कम्प्यूटर, कार्यालय इत्यादि आधुनिक सुविधाएँ स्थापित करें।  
 (2) विभाग, समय-समय पर बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों तथा निगम पर ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिन्हें अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु उपयुक्त समझे। इसके साथ-साथ ऐसी शर्तें शामिल होगी जो किसी विशिष्ट लघु खनिज अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए विशिष्ट हो।

#### अध्याय – IV

- 34. बिहार राज्य खनन निगम द्वारा क्रियाकलाप।** — (1) राज्य सरकार सभी अथवा किसी खनन क्रियाकलाप अथवा व्यापार, बिहार राज्य खनन निगम को सौंपेगा। निगम विशेषकर खनन क्रियाकलाप, लघु खनिजों के थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, भंडारण, परिवहन आदि की जिम्मेवारी ले सकेगा:

- परन्तु यदि निगम लघु खनिजों के खनन या उत्खनन की जिम्मेवारी लेने का इच्छुक हो तो वह इस नियमावली के अधीन यथापेक्षित खुली सार्वजनिक बोली में भाग लेगा।
- (2) निगम उक्त प्रयोजनार्थ किसी सरकार अथवा अर्धसरकारी अथवा प्राईवेट उपक्रम के साथ कोई व्यवस्था कर सकेगा।
- 35. निगम द्वारा विहित दरों पर खनिज का क्रय किया जाना।** — विभाग सभी नये बंदोबस्तधारियों अथवा विद्यमान बंदोबस्तधारियों या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को अपने उत्पाद का सभी या कोई अनुपात निगम को उन दरों पर, जो विहित की जाये, विक्रय करने हेतु निदेश दे सकेगा।
- 36. नए बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विहित दर।** — सभी नए बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों से उनके द्वारा उत्खनन किये गये खनिजों की आपूर्ति, प्रतियोगी बोली के माध्यम से, नियत दर पर निगम को करने की अपेक्षा करेगा।
- 37. विद्यमान बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विहित दर।** — (1) विद्यमान बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विहित दर नियत करते समय विभाग जिले के खनन पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग कर सकेगा और उत्पादन खर्च, प्रबंध प्रभार (हैंडलिंग चार्ज), परिवहन खर्च तथा किसी अन्य खर्च पर विचारण के पश्चात्, प्रस्तावित विहित दर नियत कर सकेगा।
- (2) इस प्रस्तावित विहित दर पर विभाग विद्यमान बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों से आपत्तियों की मांग कर सकेगा। और उक्त बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों की सुनवाई करने के पश्चात्, विभाग विहित दर को अंतिम रूप दे सकेगा।
- स्पष्टीकरण।** — इस नियम के परियोजनार्थ विद्यमान बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या फार्म जो इस नियमावली के आरंभ के दिन खनिज पट्टे अथवा अनुज्ञप्ति का स्वामी हो।

#### अध्याय V

#### खनन पट्टा की स्वीकृति की प्रक्रिया

- 38. ई — बोली लगाना।** — (1) खनन भूखंड अथवा इसके खनन गुच्छ के लिए सभी खनन पट्टे अधिमानतः ई—बोली लगाने के ढंग से सार्वजनिक बोली के माध्यम से स्वीकृत किए जायेंगे।
- (2) विभाग इस प्रयोजन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन जारी करेगा।
- 39. व्यक्तियों के लिए पात्रता।** — किसी व्यक्ति को खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का पात्र होने के लिए उसे—
- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए,
  - (ख) पैन कार्ड धारी होना चाहिए;
  - (ग) किसी सरकारी बकाये के भुगतान का चूककर्ता या निष्कासित नहीं होना चाहिए अथवा उसे खनन अनुज्ञप्ति से वंचित किया गया अथवा काली सूची में डाला गया नहीं होना चाहिए;
  - (घ) ऋणशोधक्षम और चरित्रवान होना चाहिए तथा किसी भी अधिनियम के अधीन किसी अपराध में सिद्धदोष किया गया नहीं होना चाहिए तथा उक्त को पुलिस द्वारा सत्यापित होना चाहिए;
  - (ङ.) अठारह वर्ष से कम आयुवाले अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को भाड़े पर नहीं रखना चाहिए अथवा नियोजित नहीं करना चाहिए।
- 40. फर्म के लिए पात्रता।** — किसी फर्म को खनन पट्टा या किसी अनुज्ञप्ति का पात्र होने के लिए उसे—
- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए;
  - (ख) आयकर विभाग से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए;
  - (ग) इस बात का शपथपत्र होना चाहिए कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है अथवा उक्त फर्म के विरुद्ध बकाया लंबित नहीं है तथा उक्त को पुलिस द्वारा सत्यापित होना चाहिए;
  - (घ) कोई खनन पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए चूककर्ता अथवा काली सूची में डाला गया अथवा वंचित किया गया नहीं होना चाहिए;
  - (ङ.) ऋणशोधक्षम होना चाहिए तथा किसी भी अधिनियम के अधीन किसी अपराध में सिद्धदोष किया गया नहीं होना चाहिए;
  - (च) अठारह वर्ष से कम आयुवाले अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को भाड़े पर नहीं रखना चाहिए अथवा नियोजित नहीं करना चाहिए।
- 41. ई — बोली प्रक्रिया।** — (1) विभाग द्वारा ऐसी जगह ई—बोली संचालित की जाएगी जहाँ इच्छुक बोली लगानेवाले भाग ले सकें। विभाग जिले में ई—बोली के संचालन हेतु जिला समाहर्ता को प्राधिकृत कर सकता है। ऐसी बोली के लिए विभाग अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- (2) बोली, खनन भूखंड वार अथवा उसके गुच्छ के आधार पर लगाई जाएगी।
  - (3) विभाग हरेक खनन भूखंड अथवा गुच्छ के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य अधिकथित करेगा। ई—बोली में इच्छुक कोई व्यक्ति/फर्म डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से न्यूनतम आरक्षित मूल्य विभाग के पास जमा करेगा।
  - (4) तत्पश्चात् सफल बोली लगानेवाले को तब में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे उचित जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण समर्पित करना आवश्यक होगा।

- (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण समर्पित करने पर विभाग खनन पट्टा निर्गत करने के लिए समाहर्ता को अनुशंसा करेगा।
- (6) सफल बोली लगानेवाले को खनन पट्टा निर्गत करने के पूर्व समाहर्ता अनुज्ञप्ति प्राधिकार के रूप में देखेगा कि –
  - (क) सफल बोली लगानेवाले ने अपेक्षित प्रतिभूति जमा कर दी है
  - (ख) सफल बोली लगानेवाले ने विभाग द्वारा बताए गए फार्मेट में बोली अवधि के लिए बैंक गारंटी जमा कर दिया है।
  - (ग) सफल बोली लगानेवाले ने खनन योजना जमा कर दी है।
  - (घ) सफल बोली लगानेवाले ने निर्धारित मुद्रांक शुल्क तथा अन्य संबंधित शुल्क जमा कर दिया है।
- (7) समाहर्ता से खनन पट्टा प्राप्त होने पर सफल बोली लगाने वाला 3 माह के अन्दर सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (8) पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने पर, सफल बोली लगानेवाला समाहर्ता को सूचित करेगा और तत्पश्चात् समाहर्ता जिला खनन पदाधिकारी को बन्दोबस्तधारी के साथ करार करने के लिए प्राधिकृत करेगा और खनन कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश निर्गत करेगा।
- (9) विभाग बन्दोबस्तधारी द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए करार प्रपत्र अधिकथित करेगा।
- (10) विभाग निर्विघ्न ई-बोली लगाने के लिए समाहर्ता को मार्गदर्शन अथवा स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सक्षम होगा।

## अध्याय VI

### लघु खनिजों का भंडारण, व्यापार, विक्रय और क्रय

42. **लघु खनिजों के व्यापार का विनियमन।** – (1) लघु खनिजों के भंडारण, व्यापार, विक्रय और क्रय का कारोबार राज्य सरकार द्वारा पट्टा, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र के विधान के माध्यम से विनियमित की जाएगी।  
(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसा अगला निदेश निर्गत कर सकेगी जो लघु खनिज के व्यापार को विनियमित करने के लिए उपयुक्त समझा जाय।
43. **थोक व्यापार।** – (1) विभाग थोक व्यापार की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले सकेगा अथवा राज्य में कुछ या सभी लघु खनिजों के थोक व्यापारी होने के लिए निगम को प्राधिकृत कर सकेगा।  
(2) बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी से, जो लघु खनिजों के खनन कार्यों की जिम्मेवारी लेता है को खनिजों का उत्खनन/विनिर्माण करने तथा निगम के पास निर्धारित दर पर जमा करने की अपेक्षा की जायेगी।  
(3) बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को लघु खनिजों को सीधे किसी व्यक्ति अथवा फर्म को बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी।  
(4) लघु खनिजों के थोक व्यापारी के रूप में निगम फुटकर विक्रेताओं, सरकार और ठेकेदारों को बाजार दरों अथवा सरकार द्वारा निदेशित दरों पर लघु खनिज बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।
44. **बफर स्टॉक।** – लघु खनिजों के मूल्यों को विनियमित करने के लिए विभाग निगम को कुछ अथवा सभी लघु खनिजों के कुछ निश्चित मात्रा के कतिपय बफर स्टॉक को रखने तथा उसे ऐसे स्थानों तथा ऐसे मूल्यों पर जो विभाग निदेशित करे, बिक्रय करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।
45. **फुटकर व्यापार।** – (1) लघु खनिजों के फुटकर व्यापार को विनियमित करने के लिए समाहर्ता जिला में फुटकर विक्रेताओं को जिन्हें लघु खनिजों के भंडारण तथा विशेष रूप से इसे लोगों को बेचने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा, फुटकर अनुज्ञप्तियाँ जारी करेगा।  
(2) समाहर्ता द्वारा सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में फुटकर अनुज्ञप्तियाँ दी जायेंगी। समाहर्ता ऐसे फुटकर विक्रेताओं की संख्या को विनिश्चित करने के लिए सक्षम होगा।  
(3) फुटकर विक्रेताओं का परिवाहक अथवा परिवहन एजेंसी होने की दशा में, उनसे उन्हें अलग से विभाग में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा की जा सकेगी।  
(4) परिवाहक सहित सभी फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों का जी0एस0टी0करण आवश्यक रूप से होना चाहिए।  
(5) विभाग फुटकर अनुज्ञप्तियों और फुटकर कारोबारियों की अन्य शर्तों को अधिकथित करेगा।
46. **पट्टा और अनुज्ञप्ति का नवीकरण।** – (1) सामान्यतया बन्दोबस्तधारी के खनन पट्टा का नवीकरण नहीं होगा। खनन पट्टा की अवधि समाप्त होने पर विभाग अथवा समाहर्ता उक्त खनन भूखंड अथवा गुच्छ को पुनः सार्वजनिक नीलामी के लिए रखेगा। परन्तु नयी नीलामी करने में अकल्पित विलंब की दशा में समाहर्ता नयी नीलामी पूर्ण होने तक के लिए पूर्व बन्दोबस्तधारी के खनन पट्टा का नवीकरण छह माह से अनधिक अवधि के लिए करेगा।  
(2) फिर भी फुटकर अनुज्ञप्ति की दशा में समाहर्ता उस अवधि के लिए फुटकर अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा जो विभाग द्वारा अपने मार्गदर्शन में उपदर्शित करे।
47. **लघु खनिजों के विक्रय मूल्य।** – (1) अंतिम उपयोगकर्ता अथवा लोगों को बेचने के लिए लघु खनिजों के विक्रय मूल्य बाजार बल द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे।



(2) फिर भी राज्य सरकार अथवा समाहर्ता, लोक हित में, बाजार मूल्य को विनियमित करने के लिए उस रीति से हस्तक्षेप करेगा, जिसे वह उचित समझे।

- 48. अनुज्ञप्तियों का अनंतरणीयता।** — इस नियमावली के अधीन निर्गत अथवा नवीकृत सभी अनुज्ञप्तियाँ अनंतरणीय होंगी।

## अध्याय VII

### ई—अपेक्षाएँ

- 49. इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के उपयोग।** — खान आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी खनन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी अन्य पणधारी से अपनी विवरणी (रिटर्न), विवरण तथा क्रियाकलाप इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने तथा इलेक्ट्रॉनिक रीति से सभी अथवा किसी कार्य की जिम्मेवारी लेने की अपेक्षा कर सकेगा।
- 50. ई—चालान।** — (1) लघु खनिजों का संचलन का, चाहे बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हो या निगम द्वारा, अनुश्रवण विभाग द्वारा विकसित ई—चालान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।  
(2) जो भी ई—चालान प्रणाली का अनुपालन करने से इनकार करता है उसे इस नियमावली के उपबंधों के अधीन अभियोजित किया जाएगा।
- 51. खनन एम.आई.एस.—** (1) विभाग सभी बन्दोबस्तधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों, निगम, और लघु खनिजों के परिवहन और व्यापार में लगे अन्य व्यक्तियों से, इस नियमावली के उपबंध के अधीन आने तथा विभाग द्वारा विकसित किए गए खनन एम.आई.एस. प्रणाली के अनुसार अपनी गतिविधियों की जिम्मेवारी लेने के लिए, अपेक्षा करेगा।  
(2) जो भी खनन एम.आई.एस. प्रणाली का अनुपालन करने से इनकार करता है उसे इस नियमावली के उपबंध के अधीन अभियोजित किया जाएगा।  
(3) विभाग अपने एम.आई.एस. के लिए विस्तृत मार्गदर्शन अधिकथित करेगा।

## अध्याय VIII

### लघु खनिजों के संचलन के लिए अनुज्ञापत्र की स्वीकृति।

- 52. लघु खनिजों का संचलन।** — (1) राज्य के भीतर अथवा राज्य से बाहर अथवा राज्य होकर किसी लघु खनिज का आयात, निर्यात अथवा परिवहन अथवा पारगमन वैध अनुज्ञापत्र/चालान/ ई—चालान और संदेय फीस (यदि कोई हो) जो विहित की जाय, के बिना नहीं किया जाएगा।  
(2) यदि लघु खनिज की किसी खेप को सड़क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहित किया जा रहा हो तो वाहन का चालक अथवा प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकार से विहित रीति से पारगमन अनुमति प्राप्त करेगा;  
(3) उप धारा (2) में निर्दिष्ट चालक अथवा व्यक्ति का उप धारा (2) के उपबंधों के अनुपालन में चूक करने की दशा में उस पर सरकार द्वारा विनिश्चित शास्ति उद्गृहीत करने के अतिरिक्त उसे इस नियमावली के उपबंध के अधीन अभियोजित किया जाएगा।
- 53. लघु खनिजों को ढोनेवाले वाहनों पर प्रतिबंध।** — (1) राज्य सरकार किसी लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर समुचित प्रतिबंध निर्धारित कर सकेगी तथा उनसे कुछ विशिष्टियों का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकेगी:  
परन्तु राज्य सरकार परिवहन वाहनों से जी.पी.एस. उपकरण अथवा ऐसे अन्य उपकरण, जो आवश्यक हो, को लगाने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।  
(2) राज्य सरकार लघु खनिज को उत्खनन/उत्पाद स्रोत से निगम और फुटकर विक्रेता के भांडागार तक परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जानेवाले वाहन/परिवहन के आकार और प्रकृति को भी विनिर्दिष्ट करेगी।
- 54. लघु खनिजों के परिवहन को विनियमित करने की शक्ति।** — (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य अथवा राज्य क्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट भाग में अथवा राज्य से होकर लघु खनिजों में से किसी अथवा सभी के संचलन अथवा आयात अथवा निर्यात को विनियमित कर सकेगी।  
(2) लघु खनिजों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विभाग चेक पोस्ट, बैरियर, धर्मकांटा इत्यादि सुविधाओं को स्थापित कर सकेगा।
- 55. अनुज्ञापत्र की अनंतरणीयता।** — इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी अनुज्ञापत्र अनंतरणीय होंगे।

## अध्याय IX

### खनन पट्टा, फुटकर अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञापत्र का निरस्तीकरण

- 56. खनन पट्टा, फुटकर अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञापत्र स्थगित अथवा रद्द करने की शक्ति—** (1) समाहर्ता अपने जिला में किसी बन्दोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी का कोई खनन पट्टा रद्द करने के लिए सक्षम होगा। वह इस नियमावली के अधीन निर्गत किसी संचलन अनुज्ञापत्र को रद्द करने के लिए सक्षम होगा।  
(2) समाहर्ता राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रतिबंधों के अधधीन सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी खनन पट्टा अथवा फुटकर अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञापत्र को स्थगित अथवा रद्द कर सकेगा और उनकी प्रतिभूति जमा/पेशगी जमा जप्त कर सकेगा:—

- (क) यदि खनन पट्टा अथवा अनुज्ञापत्र अंतरित या उप पट्टा किया जाता है अथवा उसके धारक द्वारा शिकमी दिया जाता है; अथवा
- (ख) यदि उसके धारक द्वारा देय खनन राजस्व का सम्यक् रूप से भुगतान नहीं किया जाता है; अथवा
- (ग) ऐसे पट्टाधारी, अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी अनुज्ञापत्रधारी अथवा उसके अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अनुमति से उसके नौकर अथवा अभिकर्ता अथवा उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे खनन पट्टे, किसी अनुज्ञप्ति अथवा संचलन अनुज्ञापत्र के किसी निबंधन और शर्तों को भंग करने की दशा में;
- (घ) यदि खनन पट्टाधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी अथवा संचलन अनुज्ञापत्रधारी अथवा उसका अभिकर्ता अथवा कर्मचारी अधिनियम अथवा इस नियमावली अथवा खनन विषयों अथवा खनन राजस्व से संबंधित विषयों से जुड़े और सुसंगत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय अपराध अथवा किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन किसी संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध में सिद्धदोष हो;
- (ङ) जिस उद्देश्य के लिए पट्टा, अनुज्ञप्ति अथवा संचलन अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया था वह यदि अस्तित्वहीन हो जाय;
- (च) यदि दुर्यपदेशन अथवा कपट से खनन पट्टा, अनुज्ञप्ति अथवा संचलन अनुज्ञापत्र प्राप्त किया गया हो।
- (छ) यदि बंदोबस्तधारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी इस नियमावली में उल्लिखित किसी शर्तों का उल्लंघन किया हो।
- (ज) यदि कोई बंदोबस्तधारी तीन माह में पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल रहता है या उसमें उल्लिखित किसी शर्त का अतिक्रमण करता है।
- (झ) यदि बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी खनन प्रचालन, करार हस्ताक्षर करने के तिथि से तीन माह के भीतर, आरंभ करने में असफल रहता है;
- (ञ) यदि, किसी अन्य कारण से समाहर्ता का प्रथमदृष्टया यह समाधान हो जाये कि पट्टा या अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र रद्द किए जाने के योग्य है।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी कार्यवाई के लिए, बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रतिकर या प्रतिदाय या जमाराशि, जो कुछ भी हो, का पात्र नहीं होगा।

(4) ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम, इस नियमावली और खनन पट्टा या किसी अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र के किसी अन्य शर्त के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता लगने की स्थिति में, राज्य सरकार या समाहर्ता उक्त खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति/संचलन अनुज्ञापत्र को रद्द करने के अलावा उपयुक्त वित्तीय शास्तियों और/या आपराधिक अभियोजन भी अधिरोपित कर सकेंगे।

(5) ऐसी कोई भी शास्ति का उद्ग्रहण लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अधिनियम 4/1914) के अधीन वसूलनीय होगा।

**57. किसी पट्टा या अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने की प्रक्रिया।** – (1) इस अधिनियम या इस नियमावली के किसी उल्लंघन की बाबत किसी खनन पदाधिकारी से प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, समाहर्ता उक्त बंदोबस्तधारी या अनुज्ञप्तिधारी को कारण दर्शाने हेतु 15 दिनों का समय देते हुए, एक नोटिस निर्गत करेगा।

(2) बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश में समाहर्ता यह इंगित करेगा कि लघु खनिज को स्टॉक और अन्य परिवहन जप्त अथवा नीलाम किया जाना चाहिए अथवा और उस प्रकार प्राप्त राशि बंदोबस्तधारी को वापस होनी चाहिए या नहीं।

(3) समाहर्ता, बंदोबस्तधारी को यह भी निदेश दे सकेगा कि वह स्टॉक, खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलंबन के कारण, निगम के पास, उस मूल्य पर जो निगम द्वारा विनिश्चित किया जाय, जमा कर दिया जाय। यदि बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी समाहर्ता के आदेश का क्रियान्वयन करने में असफल होता है तो समाहर्ता निगम के पास लघु खनिजों को जमा करवायेगा और उसका खर्च बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी से वसूल करेगा।

(4) जहाँ बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी उक्त नोटिस के जबाव में उपस्थित होने से चूकता है, वहाँ समाहर्ता एकपक्षीय आदेश पारित करने को स्वतंत्र होगा।

**58. नवीकरण एवं प्रतिकर के अधिकार का वर्जन।** – कोई भी व्यक्ति, जिसे पूर्व में पट्टा या अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया हो, उसके किसी नवीकरण का दावा, अधिकार के रूप में करने का हकदार नहीं होगा उसके प्रवृत्त रहने की अवधि के समापन पर खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र के नवीकरण करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप नुकसान या अन्यथा के लिए कोई दावा संस्थित नहीं होगा।

**59. सभी या कोई भी अनुज्ञप्ति वापस लेने या उसका नवीकरण नहीं करने की राज्य सरकार की शक्ति।** – (1) राज्य सरकार समूचे बिहार राज्य या उसके किसी भाग में किसी बंदोबस्तधारी या अनुज्ञप्तिधारी को निर्गत खनन पट्टा या कोई अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञप्ति किसी समय या तो वापस लेने या उसका नवीकरण नहीं करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गई किसी कार्रवाई के लिए, उसके परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा वसूलनीय किसी रकम की कटौती के बाद, अग्रिम रूम में भुगतान किए गए किसी फुटकर अनुज्ञप्ति फीस या जमाराशि को छोड़कर, कुछ भी संदत्त नहीं किया जाएगा।

- 60. प्रबंधन ग्रहण करने की समाहर्ता की शक्ति।** – यदि कोई बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी या इस नियमावली के अधीन निर्गत फुटकर अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसपर अधिरोपित किसी शर्त का अनुपालन करने में चूकता है या इस नियमावली के अधीन समाहर्ता द्वारा निर्गत ऐसे युक्तियुक्त निदेशों का पालन करने से इंकार किए जाने पर या खनन पट्टा-अवधि की समाप्ति या फुटकर अनुज्ञप्ति के समापन या फुटकर अनुज्ञप्ति की वापसी होने पर, समाहर्ता, किसी भी समय, ऐसे खनन पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति या विशेषाधिकार रद्द करते हुए या उसके रद्दकरण के बिना –

- (क) उस स्थापना के स्वामी की हानि और जोखिम पर ऐसे खनन कार्यों का प्रबंधन ग्रहण कर सकेगा; या
- (ख) उस स्थापना के स्वामी की हानि और जोखिम पर ऐसे स्थापना का प्रबंधन ग्रहण कर सकेगा; या
- (ग) खनन पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति या विशेषाधिकार की अनवसित अवधि के लिए उस स्थापना को, उसके स्वामी की हानि और जोखिम पर, किसी अन्य व्यक्ति या निगम को अंतरित कर सकेगा।

- 61. लघु खनिज अधियाचना करने की समाहर्ता की शक्ति।** – (1) ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी प्राकृतिक आपदा या भारी कमी या ऐसी अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में अथवा बफरस्टॉक बनाए रखने के लिए समाहर्ता बंदोबस्तधारी से लघु खनिज की एक विनिर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन अथवा उत्खनन करने एवं ऐसे स्थान एवं ऐसे दर पर वितरण करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(2) ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी प्राकृतिक आपदा या भारी कमी या ऐसी किसी अन्य आकस्मिकताओं की स्थिति में, समाहर्ता फुटकर अनुज्ञप्तिधारी से किसी लघु खनिज की विनिर्दिष्ट मात्रा ऐसे स्थान एवं ऐसे दर पर वितरण करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

- 62. बंदोबस्तधारी या फुटकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कारोबार छोड़ने का विकल्प।** – (1) कोई बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी फुटकर अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, खनन पट्टा अवधि या अनुज्ञप्ति अवधि के किसी भी समय समाहर्ता को तीन महीने का नोटिस देते हुए कारोबार छोड़ने का विकल्प दे सकेगा। फिर भी, यह विकल्प वैसे बंदोबस्तधारियों के लिए नहीं है जिन्होंने भुगतान नहीं किया है, इसलिए अपनी बोली की रकम या बंदोबस्ती की रकम का भुगतान नहीं किया है अथवा खनन पट्टे/अनुज्ञप्तिधारी की किसी शर्त का उल्लंघन किया है।

(2) समाहर्ता ऐसे बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को कारोबार छोड़ने की अनुमति दे सकेगा और यथा वसूलनीय ऐसे किसी बकायों की कटौती कर बंदोबस्तधारी या फुटकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस कर सकेगा।

(3) समाहर्ता, तदनंतर, यथास्थिति एक नई बोली या नए फुटकर अनुज्ञप्ति के लिए व्यवस्था की शुरुआत करेगा।

(4) धोखाधड़ी या खनन अथवा पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन या प्रतिवेदित की गई किसी अन्य अनियमितताओं की स्थिति में, कारोबार छोड़ने का कोई विकल्प बंदोबस्तधारी अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध नहीं रहेगा और उनकी प्रतिभूति जमा जप्त हो जाएगी।

- 63. निदेश देने की समाहर्ता की शक्ति।** – (1) जहाँ खनन पट्टा रद्द कर दिया गया हो या रद्द किया जाना प्रस्तावित हो, समाहर्ता, बंदोबस्तधारी को उत्खनन करते रहने और ऐसे लघु खनिज को ऐसी मात्रा में उत्पादन करने तथा उसको ऐसे स्थान पर जमा करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएँ न की जायें।

(2) ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, समाहर्ता किसी बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को कोई विनिर्दिष्ट कार्य करने या नहीं करने का कोई निदेश दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला में विहित दरों पर लघु खनिजों की उपलब्धता हो और अधिनियम एवं इस नियमावली के उपबंधों का कोई उल्लंघन नहीं हो।

- 64. खनन पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति निलंबित करने/रद्द करने की खान आयुक्त की शक्ति।** – इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खान आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी परिवाद पर या किसी खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर इस नियमावली के अधीन निर्गत किसी खनन पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति किसी अन्य अनुज्ञप्ति/संचलन अनुज्ञापत्र को रद्द करने या निलंबित करने हेतु कदम उठा सकेगा:

परन्तु वह कोई आदेश पारित करने के पूर्व ऐसे बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी को अपने मामले को प्रस्तुत करने हेतु एक युक्तियुक्त अवसर देगा।

**अध्याय X**  
**खनन राजस्व**

- 65. खनन राजस्व की प्रकृति एवं घटक।** – खनन राजस्व निम्नलिखित शीर्षों के अधीन उद्गृहीत एवं वसूल किये जायेंगे, यथा –
- (क) बोली आगम
  - (ख) फुटकर अनुज्ञप्तियों से फीस
  - (ग) स्वामिस्व
  - (घ) विशेष फीस
  - (ङ) संचलन अनुज्ञापत्रों आदि सहित अनुज्ञापत्रों से फीस
  - (च) मालिकाना फीस
  - (छ) जुर्मानों, शास्तियों और अन्य विविध प्राप्ति आदि के माध्यम से प्रोद्भवन्; और
  - (ज) कोई अन्य शुल्क, फीस या अधिभार जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिरोपित करे।
- 66. किसी रिट याचिका, वाद, आदि के लंबित रहने को विचार में लाये बिना भुगतान किये जाने वाले खनन राजस्व।** – इस बात के होते हुए भी कि कोई रिट याचिका प्रस्तुत की गयी हो या किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित की गयी हो या कोई अपील न्यायाधिकरण या खान आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी हो या कोई संशोधन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, इस अधिनियम या इस नियमावली के द्वारा या अधीन इस निमित्त सशक्त किसी पदाधिकारी या प्राधिकार द्वारा किये गये या पारित आदेश या मांग के परिणामस्वरूप इस अधिनियम या इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को बकाया कोई रकम ऐसी माँग या आदेश के अनुसार भुगतेय होगा जब तक और जहाँ तक कि सक्षम प्राधिकार या न्यायालय द्वारा ऐसे भुगतान पर रोक न लगा दिया गया हो।
- 67. आयात, निर्यात, परिवहन और उत्खनन पर फीस अधिरोपित करने की शक्ति।** – (1) राज्य सरकार द्वारा यथानिर्देशित ऐसे दर या दरों पर यथास्थिति कोई फीस या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र पर अधिरोपित किया जा सकेगा—
- (क) आयातित कोई लघु खनिज, या
  - (ख) निर्यातित कोई लघु खनिज, या
  - (ग) परिवहित कोई लघु खनिज या
  - (घ) इस अधिनियम के अधीन निर्गत या नवीकृत किसी खनन पट्टा के अधीन उत्खनित कोई लघु खनिज, या
  - (ङ.) किसी खान या दलित्र में उत्खनित या उत्पादित कोई लघु खनिज
- (2) राज्य सरकार द्वारा यथानिर्देशित ऐसी दर या दरों पर कोई शुल्क इस नियमावली के उपबंधों के अधीन किसी लघु खनिजों पर या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए अधिरोपित किया जा सकेगा।
- 68. लघु खनिजों से स्वामिस्व।** – (1) सभी लघु खनिज राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित तथा समय-समय पर यथा संशोधित दर पर उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाले स्वामिस्व के अधधीन होंगे।
- (2) सभी स्वामिस्व निगम द्वारा भी संगृहीत और प्रत्येक माह राज्य सरकार को जमा किये जा सकेंगे।
- (3) विभाग स्वामिस्व के संबंध में यथावश्यक अन्य मार्गदर्शन अधिकथित कर सकेगा।
- 69. सरकारी परियोजनाओं से मालिकाना फीस।** – (1) अपने स्कीमों या परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने वाले सभी सरकारी विभाग विशिष्टतः निर्माण विभाग ऐसे लघु खनिजों के अपने आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों से मालिकाना फीस की कटौती करेंगे।
- (2) ऐसी मालिकाना फीस की सामान्य दर दो प्रतिशत होगी और विभाग द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता और ठेकेदारों से उसकी कटौती की जायेगी तथा जिला खनन पदाधिकारियों के पास जमा की जाएगी।
- परन्तु राज्य सरकार समय समय पर मालिकाना फीस में वृद्धि या कमी कर सकती है।
- 70. रिटर्न सौंपना।** – (1) प्रत्येक बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी खनन कार्यकलाप, खनिज उत्खनन और खनिजों के प्रेषण से संबंधित अपने सभी संव्यवहारों और प्रत्येक माह के लिए विशेष रूप से विहित किसी अन्य संव्यवहारों की बाबत विहित प्राधिकार को ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से वास्तविक एवं पूर्ण रिटर्न सौंपेगा जो विहित की जाय।
- (2) यदि बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी विहित समय के भीतर रिटर्न सौंपने में असफल रहता है, तो वह इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन अभियोजित किया जाएगा।
- 71. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्न दाखिल करना, चालान द्वारा भुगतान करना या विवरण देना।** – खान आयुक्त अधिसूचना द्वारा बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी के किसी भी वर्ग से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्न दाखिल करने, चालान द्वारा भुगतान करने या विवरण देने की अपेक्षा कर सकेंगे। उस स्थिति में जहाँ ऐसी अधिसूचना निर्गत हो गयी हो, उसमें विनिर्दिष्ट पट्टाधारी/ बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी के वर्ग को विशेष रूप से अभिहित

स्थल या विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना रिटर्न दाखिल करना, चालान द्वारा भुगतान करना या विवरण देना अनिवार्य होगा।

- 72. स्वामिस्व और उस पर ब्याज का भुगतान।** – प्रत्येक बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी, चालान/ई-चालान के माध्यम से विहित रीति से भुगतान किये जाने वाले देय स्वामिस्व का भुगतान करेगा। नियत तिथि को भुगतान करने में चूक किये जाने की दशा में, वे विहित रीति से ब्याज का भुगतान करने के दायी होंगे। ब्याज चूँकि नागरिक दायित्व है, इसलिए उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए नोटिस निकाला जाना अपेक्षित नहीं है। वस्तुतः ब्याज के भुगतान की आवश्यकता वाली परिस्थितियों के अधीन, पट्टाधारी/बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी से उम्मीद की जाती है वे इसे स्वप्रेरणा से अभिकलित करें और इसका भुगतान करें तथा ऐसे भुगतानों के साक्ष्य के रूप में चालान प्रस्तुत करें।
- 73. रिटर्न की संवीक्षा।** – (1) खनन पदाधिकारी विहित समय के भीतर एवं विहित रीति से निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक रिटर्न एवं भुगतान की संवीक्षा करेंगे कि –  
 (क) उसमें निहित सभी परिगणनायें अंकगणितीय रूप से सही हैं;  
 (ख) स्वामिस्व, मालिकाना फीस की रकम, खनिजों के निष्कर्षण, भुगतेय स्वामिस्व और भुगतेय ब्याज, यदि कोई हो, सही-सही एवं समुचित रूप से अभिकलित कर लिए गये हैं;  
 (ग) स्वामिस्व और भुगतेय ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान से संबंधित यथाविहित साक्ष्य सौंप दिया गया है;  
 (2) यदि उप धारा (1) के अधीन संवीक्षा पर खनन पदाधिकारी कोई गलती पाता है, तो वह संबंधित/बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी को 7 दिनों के भीतर देय स्वामिस्व या ब्याज का भुगतान करने का निदेश देते हुए विहित प्रपत्र में एक नोटिस तामीला करायेगा।  
 (3) यदि विहित प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान है कि किसी बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी ने स्वामिस्व का अपवंचन करने के आशय से गलत रिटर्न प्रस्तुत किया है, तो विहित प्राधिकार सुने जाने का उसे एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी से देय स्वामिस्व, यदि कोई हो, की रकम अपने सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि से निर्धारित करेगा।  
 (4) यदि बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी से अथवा फुटकल अनुज्ञप्तिधारी खनन पदाधिकारी के आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वह नियम 80 के अधीन अभियोजित किया जाएगा।
- 74. एकल बैंक खाता।** – (1) सभी बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक रूप से उक्त पट्टे या फटकर अनुज्ञप्ति अथवा संचलन अनुज्ञापत्र से संबंधित सभी अपने प्रचालन के लिए केवल एकल बैंक खाता प्रचलित करेंगे।  
 (2) बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक रूप से उक्त बैंक खाते की जानकारी समाहर्ता, जिले के खनन पदाधिकारी, खान निदेशक तथा खान आयुक्त को देंगे।  
 (3) कोई व्यक्ति, जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, नियम 80 के अधीन अभियोजित किया जायेगा।

#### अध्याय XI

#### अपराध एवं शास्तियाँ—

- 75. अविधिपूर्ण आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, बिक्री आदि के लिए शास्ति।** – जो कोई भी, इस अधिनियम की धारा 4 (1) और धारा 4 (1 क) या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली या किये गये आदेश या निर्गत अधिसूचना के उल्लंघन में या इस नियमावली के अधीन किसी खनन पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र या किसी अन्य अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन में या इस नियमावली के अधीन निर्गत वैध खनन पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र के बिना—  
 (क) किसी लघु खनिज का उत्खनन करता है, उसका उत्पादन करता है, रखता है, खरीदता है, विक्रय करता है, वितरित करता है, संग्रह करता है, आयात करता है, निर्यात करता है या उसका परिवहन करता है, या  
 (ख) वाहन परिवहन की अधिकृत ढोने की क्षमता से बहुत अधिक लघु खनिजों का परिवहन करता है, या  
 (ग) इस तरह से किसी लघु खनिज के उत्खनन, उत्पादन, परिवहन या व्यवसाय में लिप्त रहता है जिससे खनन क्षेत्र या उसके बाहर या उसके आस-पास काम करने वाले किसी व्यक्ति पर जीवन संकट की संभावना हो जाये;  
 (घ) कोई प्लांट या मशीनरी अथवा क्रशर निर्मित स्थापित करता है;  
 तो वह पाँच वर्षों की अवधि के कारावास और कम-से-कम एक लाख रुपये, जो पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकेगा, के जुर्माना से दंडनीय होगा।
- स्पष्टीकरण।** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, परिवहन के किसी स्वामी या लघु खनिज के बंदोबस्तधारी को भी अभियोजित किया जा सकेगा, यदि यह स्थापित हो जाता है कि ऐसा उल्लंघन परिवहन चालक के अतिरिक्त ऐसे स्वामी या बंदोबस्तधारी की पूरी जानकारी में हो रहा है।
- 76. कंपनियों द्वारा अपराध करना।** – (1) यदि इस नियमावली के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है, तो अपराध करने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी स्वयं और कंपनी का प्रभारी या कंपनी

के लिए जिम्मेवार प्रत्येक व्यक्ति को इस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी तय मानी जायेगी और तदनुसार दंडित किया जायेगा:

परन्तु जहाँ कंपनी में विभिन्न स्थापनाएँ हैं या किसी स्थापना में विभिन्न शाखाएँ या किसी शाखा में विभिन्न इकाई हैं तो संबंधित मुख्य कार्यपालक और कारबार के संचालन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में कंपनी द्वारा नामित ऐसी स्थापना, शाखा, इकाई का प्रभारी व्यक्ति ऐसी स्थापना, शाखा या इकाई के संबंध में उल्लंघन के लिए जिम्मेवार होगा:

परन्तु यह और कि इस उप धारा की कोई भी बात जिम्मेवार ऐसे किसी व्यक्ति को कोई दंड नहीं देगी यदि वह यह सिद्ध करता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था और उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग कर चुका है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराध कंपनी द्वारा किया गया हो या सिद्ध हो कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है और यह कि कंपनी के ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी की ओर से कर्तव्य में उपेक्षा से ऐसा अपराध हुआ माना जा सकने वाला है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही चलाई जाएगी और तदनुसार दंडित किये जायेंगे।

(3) यह धारा ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं होगी जहाँ अधिकांश शेयरधारिता केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा या ऐसी कंपनियों द्वारा धारित हो जिसे राज्य सरकार छूट दे।

**स्पष्टीकरण** — इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'कंपनी' से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और जिसमें सम्मिलित है एक फर्म या अन्य व्यष्टि—संगम; और फर्म के संबंध में 'निदेशक', से अभिप्रेत है फर्म में भागीदर।

**77. कतिपय मामलों में अपराध करने से संबंधित उपधारणा।** — इस नियमावली के किसी सुसंगत उपबंध के अधीन अभियोजन में, जबतक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये यह उपधारित किया जायेगा कि अभियोजित व्यक्ति ने किसी लघु खनिज के कब्जा या विनिर्माण या उत्खनन के परिवहन के लिए ऐसे लघु खनिज से संबंधित उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया है, जिसका संतोषप्रद वृत्तांत देने में वह असक्षम है।

**78. लघु खनिजों में विजातीय अवयवों की मिलावट करने के लिए शास्ति।** — जो कोई भी, किसी लघु खनिजों में इसकी गुणवत्ता को कम करने के आशय से कोई विजातीय अवयव मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता है, पाँच वर्षों की अवधि के कारावास और कम-से-कम एक लाख रुपये जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, के जुर्माना से दंडनीय होगा।

**79. प्रतिकर चुकाने के लिए समाहर्ता द्वारा आदेश।** — (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समाहर्ता इस नियमावली के अधीन आदेश पारित करते समय, यदि उसका समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को बंदोबस्तधारी/ अनुज्ञप्तिधारी, के कार्य के कारण नुकसान हुआ है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में एक उचित रकम चुकाने का आदेश दे सकेगा।

(2) बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत उक्त प्रतिकर रकम का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में, समाहर्ता उक्त रकम प्रभावित व्यक्ति को दे सकेगा और उसके बाद उक्त प्रतिकर रकम लोक माँग के रूप में लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़िसा अधिनियम IV/1914) के अधीन वसूल कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

परन्तु कोई भी अपील इस नियमावली के अधीन किये गये किसी आदेश के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा जबतक कि अपीलकर्ता द्वारा उप धारा (1) के अधीन भुगतान किये जाने वाले आदेशित रकम का 50% न्यायालय में जमा न किया जाये।

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि के समापन पर अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह संतुष्ट हो जाये कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

**80. बंदोबस्तधारी, अनुज्ञप्तिधारी आदि के दुर्यवहार के लिए शास्ति।**—जो कोई भी इस नियमावली के अधीन प्रदत्त या निर्गत खनन पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र धारक या पणधारी या ऐसे धारक के नियोजन रहते हुए उसके निमित्त कार्य करता हो,

(क) ऐसी करार या अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र की माँग करने हेतु सम्यक् रूप से सशक्त किसी खनन पदाधिकारी/या पुलिस अधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा संबंधित अनुज्ञप्ति या संचलन अनुज्ञापत्र की माँग जाने पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ख) इस नियमावली में पट्टा या फुटकर अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र जो अन्यथा उपबंधित नहीं है की शर्तों के उल्लंघन में जानबूझ कर कुछ करता है या कुछ छोड़ देता है; या

(ग) किसी खनन पदाधिकारी द्वारा उसके परिसरों का निरीक्षण किये जाने के दौरान सहयोग करने में असफल रहता है, या

- (घ) किसी खनन पदाधिकारी या समाहर्ता द्वारा पारित विधिपूर्ण आदेश की जान बूझकर किसी अवज्ञा करता है; या
- (ङ) रिटर्न सौंपने में असफल रहता है— निम्नलिखित दंडित किया जायेगा:—
- (i) (1) खंड (क) के अधीन आने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम पचास हजार रुपये के जुर्माना से जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा;
- (ii) (2) खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में कम से कम दो वर्षों की अवधि के कारावास, जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा साथ ही साथ कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना से जो जुर्माना दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।
- 81. खनन या खनन व्यवसाय में अवयस्कों को नियोजित करने के लिए शास्ति।** — यदि कोई व्यक्ति किसी लघु खनिज के उत्खनन, उत्पादन, विक्रय, कब्जा, परिवहन या वितरण के प्रयोजनार्थ 18 वर्षों से कम आयु के किसी अवयस्क को नियोजित करता है, तो उसे ऐसी कारावास की सजा से जो तीन वर्षों से अन्यून किन्तु पाँच वर्षों की अवधि बढ़ायी जा सकेगी और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना से, जो पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।
- 82. हमला एवं बाधा के लिए शास्ति।** — भारतीय दंड संहिता, 1860 (XLV/1860) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, जो किसी खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी पर उनके सरकारी दायित्वों के निर्बहन में हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है या बाधा पहुँचाता है या बाधा पहुँचाने का प्रयास करता है, तो वह न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि किन्तु जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, के कारावास और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना, जो पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।
- 83. स्वामिस्व, फीस या फीस नहीं दिये जाने पर शास्ति।** — यदि कोई व्यक्ति कोई स्वामिस्व, शुल्क या फीस,, जिसे इस अधिनियम के अधीन उसे अदा करना है अदा करने में असफल रहता है वह कम से कम तीन वर्षों की अवधि के कारावास जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा जा सकेगा और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना, जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।
- 84. अपराध करने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले परिसरों आदि की अनुमति देने के लिए शास्ति।** — जो कोई भी, चाहे इस नियमावली के अधीन बंदोबस्तधारी/अनुज्ञापिधारी हो या अन्यथा, और किसी घर, कमरा, अहाता, जगह, पशु या सवारी जिसके नियंत्रण या उपयोग में हो, जानबूझ कर किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने की अनुज्ञा देता है, उसी रीति से दंडनीय होगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया हो।
- 85. अपराध करने का प्रयास के लिए शास्ति।** — जो कोई भी इस नियमावली के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने की कोशिश करता है इस नियमावली के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के आधा का भागी होगा।
- 86. खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी द्वारा कर्तव्य करने से इंकार करने पर उनपर शास्ति।** — कोई खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो, बिना विधिपूर्ण कारण के, अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने से इंकार करता है या स्वयं को उससे अलग करता है, जब तक कि खान आयुक्त या समाहर्ता द्वारा लिखित में ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ततः अनुमति न दी गयी हो, या जब तक कि उसने ऐसा करने के अपने आशय को लिखित में दो महीने के नोटिस के रूप में अपने सरकारी वरीय पदाधिकारी को न दे चुका हो या जो कायरता का दोषी होगा, कारावास से जो छः महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माना, जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
- 87. अन्यथा उपबंधित से भिन्न अपराधों के लिए शास्ति।** — जो कोई भी इस नियमावली या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के किसी उपबंधों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है और ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दंड अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो, कम से कम छः माह की अवधि के कारावास से बढ़ाकर दो वर्षों तक किया जा सकेगा या कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना जो बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
- 88. पूर्विक दोषसिद्धि के बाद बर्धित दंड।** — यदि कोई व्यक्ति, इस नियमावली के अधीन दंडनीय अपराध से पूर्व में दोषसिद्ध हो गया है; तत्पश्चात् फिर इस नियमावली के अधीन अपराध करता है और दोषसिद्ध होता है, तो वह पहली दोषसिद्धि के लिए उपबंधित दंड के दुगुने का भागी होगा।
- 89. अपराधों का अप्रशमन।** — अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अपराध अप्रशम्य होगा।

## अध्याय XII

### समाहर्ता द्वारा अधिहरण आदि

- 90. अधिहरण के लिए दायी चीजें।** — जब कभी कोई अपराध किया गया हो, जो अधिनियम और इस नियमावली के अधीन दंडनीय हो, निम्नलिखित चीजे अधिहरण हेतु दायी होगी, यथा—

- (क) कोई लघु खनिज;
- (ख) कोई प्लांट या मशीनरी;
- (ग) कोई पशु, वाहन, पात्र या अन्य सवारी जिसका उपयोग किसी लघु खनिज के ढोने या उत्खनन करने या उत्पादन करने या विनिर्माण करने के लिए किया गया हो।
- (घ) कोई भूमि और/या परिसर या उसका कोई भाग जिसका उपयोग किसी लघु खनिज के भंडारण या उत्पादन या उत्खनन के लिए किया जा सका हो।

**91. जिला समाहर्ता द्वारा लघु खनिजों के अधिहरण एवं नीलामी की प्रक्रिया।** – (1) जहाँ कोई लघु खनिज किसी खनन पदाधिकारी या पुलिस द्वारा जब्त किया जाता है, तो वह जिला समाहर्ता को इसका प्रतिवेदन सौंपेगा और इसके अधिहरण और नीलामी का अनुरोध करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, जिला समाहर्ता यदि संतुष्ट हो कि कोई अपराध इस नियमावली के अधीन किया गया है, चाहे ऐसे अपराध करने के लिए अभियोजन संस्थित हो या न हो और चाहे मामला किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो या न हो, ऐसे लघु खनिज के अधिहरण एवं नीलामी के लिए कार्यवाही कर सकेगा;

(3) समाहर्ता तदन्तर उक्त बोली से संबंधित आपत्ति दर्ज करने के लिए और उपस्थित होने के लिए संबंधित व्यक्ति को सात दिनों का नोटिस देते हुए आसन्न नीलामी के बारे में सूचना प्रदायक सार्वजनिक नोटिस निर्गत करेगा।

(4) यदि सात दिनों के अंतर्गत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो समाहर्ता उक्त लघु खनिजों को अदावाकृत समझेगा और तब उक्त लघु खनिज के अधिहरण का आदेश देने की कार्यवाही करेगा। इसके बाद, वह भावी बोली लगानेवालों के लिए सात दिनों का समय देते हुए सार्वजनिक नीलामी नोटिस निर्गत करेगा और तब सबसे अधिक बोली लगाने वाले के साथ वह नीलामी तय करेगा। आगम राशि को तब सरकारी कोषागार में जमा किया जायेगा। नीलामी विनिश्चित करने के पूर्व समाहर्ता यह निदेश देगा कि समपहृत लघु खनिज का कतिपय उनकी अनुसूचित दरों पर संबंधित स्थानीय विभाग को दिया जाय। समपहृत लघु खनिज का अवशेष भाग सबसे उँची बोली लगाने वाले की दी जाय।

(5) जहाँ, उक्त नियम (2) के अधीन निर्गत सार्वजनिक नोटिस के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है जो दावा करता है कि अधिहृत लघु खनिज उसका है, तब समाहर्ता उसके दावा को अस्वीकार या स्वीकार करते हुए उक्तियुक्त आदेश पारित करेगा। यदि दावा समाहर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो समाहर्ता उपनियम (4) के अनुसार नीलामी के लिए कार्यवाही करने की कार्यवाही कर सकेगा। फिर भी समाहर्ता आगम राशि को सरकारी कोषागार में इस शर्त के साथ जमा कर सकेगा कि यदि आपत्तिकर्ता अपील में जाता है और किसी न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करता है, तो उक्त राशि उक्त आपत्तिकर्ता को वापस लौटा दी जायेगी।

(6) जहाँ, समाहर्ता द्वारा प्राप्त आपत्ति के परिणामस्वरूप, समाहर्ता आपत्तिकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करता है और समझता है कि अधिहृत लघु खनिज आपत्तिकर्ता का है, समाहर्ता, उस जिला में उक्त लघु खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के अभिप्राय से, उपधारा (4) के अनुसार नीलामी प्रक्रिया की कार्यवाही कोभी कर सकेगा और उस नीलामी में इस प्रकार प्राप्त रकम उक्त दावेदार को दिया जा सकेगा।

(7) जहाँ उपर्युक्त उप नियम (6) के अधीन उसके आदेश के परिणाम स्वरूप उप प्रकार समपहृत लघु खनिज किसी एफ0आई0आर0 अथवा अपराधिक कार्यवाही के अधीन हो वहा समाहर्ता अभी भी नीलामी कर सकेगा किन्तु आगम को इस शर्त के साथ सरकारी कोषागार में जमा कर देगा की यदि कोई आपत्ति कर्ता अपील में जाता है और किसी न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त राशि उक्त व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

(8) जिला समाहर्ता ऐसे अधिहरण के एक महीने के भीतर खान आयुक्त को अधिहरण की सभी विशिष्टियों का पूर्ण प्रतिवेदन सौंपेगा।

**स्पष्टीकरण।** – इस नियम के प्रयोजनार्थ, सार्वजनिक नीलामी, ई-नीलामी के माध्यम से या उसके बिना हो सकेगी।

**92. जिला समाहर्ता द्वारा लघु खनिजों से भिन्न अन्य वस्तुओं की अधिहरण और नीलामी की प्रक्रिया।** – (1) जहाँ लघु खनिजों से भिन्न कोई चीज जो इस नियमावली के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, इस नियमावली के उपबंधों के अधीन जब्त किया या रोक रखा जाता है, ऐसी वस्तु या परिवहन या पात्र या पशु जब्त करने वाले या रोक रखने वाला पदाधिकारी, बिना किसी युक्तियुक्त बिलम्ब के, उस जिला समाहर्ता को प्रतिवेदन सौंपेगा जिसकी उक्त क्षेत्र पर अधिकारिता हो।;

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, जिला समाहर्ता यदि संतुष्ट हो कि कोई अपराध इस नियमावली के अधीन किया गया है, चाहे ऐसे अपराध करने के लिए अभियोजन संस्थित हो या न हो और चाहे मामला किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो या न हो, ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण एवं नीलामी के लिए कार्यवाही कर सकेगा;

(3) समाहर्ता, उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित करने के पहले, संबंधित व्यक्ति को सुने किये जाने के लिए सात दिनों का नोटिस देगा और वह उसे उपस्थित होने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस भी निर्गत करेगा;



(4) यदि उक्त व्यक्ति उपस्थित होता है और अपना जवाब दाखिल करता है, तो समाहर्ता उसपर उसके दावे को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा। यदि समाहर्ता उसके दावे को अस्वीकार करता है, तो वह उक्त चीजों के अधिहरण और इसकी सार्वजनिक नीलामी के लिए आदेश देगा।

(5) जहाँ संबंधित व्यक्ति उक्त नोटिस के परिणामस्वरूप उपस्थित नहीं होता है, तब समाहर्ता एकपक्षीय आदेश पारित करने को स्वतंत्र होगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन अधिहरण का आदेश करते समय, यदि जिला समाहर्ता की यह राय हो कि जनहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह उक्त अधिहृत चीज या उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने के लिए और आगम राशि को राज्य सरकार के कोष में जमा करने का आदेश दे सकेगा।

(7) जिला समाहर्ता ऐसे अधिहरण के एक महीने के भीतर खान आयुक्त को अधिहरण की सभी विशिष्टियों का पूर्ण प्रतिवेदन सौपेगा।

**स्पष्टीकरण।** — इस नियम के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक नीलामी, ई—नीलामी के माध्यम से या उसके बिना हो सकेगी।

**93. सार्वजनिक अथवा अपाति मामलों या जमाखोरी रोकने के लिए अधिहरण।** — जहाँ समाहर्ता यह महशूस करता है कि लघु खनिज की कमी है और प्राकृतिक आपदा के कारण अथवा बंदोबस्तीधारी/अनुज्ञप्तिधारी के अपना खनन/विनिर्माण का क्रियाकलाप अचानक छोड़ देने के कारण अथवा लघु खनिजों के जमाखोरी के कारण है तो समाहर्ता निम्नलिखित कर सकेगा:—

(क) संक्षिप्त: ऐसे समयक रूप से उत्खनित/विनिर्मित खनिजों का बिक्रय सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से या निगम को कर सकेगा और उक्त राशि का भुगतान उक्त बंदोबस्तधारी को कर सकेगा; या

(ख) ऐसे उत्खनित/विनिर्मित खनिजों को तुरन्त खुली बाजार में अथवा निगम द्वारा नियत दरों पर निगम को बेच देने हेतु बंदोबस्तधारी को निदेश दे सकेगा ताकि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके:—

(ग) ऐसे लघु खनिजों को सरकारी विभागों को उनकी अनुसूचित दरों पर तुरन्त बेच देने हेतु बंदोबस्तधारी को निदेश दे सकेगा।

**94. बैंक खाते को फ्रिज करने की शक्ति।** — (1) जहाँ समाहर्ता को खनन पदाधिकारी या पुलिस अधिकारी के प्रतिवेदन पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी का बैंक खाता सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु अथवा अभियोजन की सहायता के लिए फ्रिज करना है वह तुरन्त संबंधित बैंक ऐसे बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी का बैंक खाता अगले आदेश तक फ्रिज करने का निदेश देते हुए एक आदेश करेगा।

(2) कोई बैंक अथवा उसका कोई कर्मचारी, जो समाहर्ता के उपरिलिखित निदेश का पालन करने से इंकार करता है, नियम 80 के अधीन अभियोजित किया जाएगा।

**95. साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज की अपेक्षा।** — (1) जहाँ कोई लघु खनिज या कोई अन्य चीज अधिहृत की गयी हो और आपराधिक अभियोजन शुरू कर दिया गया हो, तो भी आपराधिक अभियोजन के प्रदर्श के रूप में उपयोग करने के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा तैयार एक सूची, फोटो, विडियो ग्राफ के प्रारूप में प्रमाणस्वरूप फोटो के रूप में पर्याप्त साक्ष्य रखते हुए समाहर्ता द्वारा ऐसे लघु खनिजों की अभी भी नीलामी की जा सकेगी।

(2) समाहर्ता तब संबंधित न्यायालय के समक्ष उक्त नीलामी के बारे में एक प्रतिवेदन दाखिल करवाएगा और उक्त प्रतिवेदन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य या/और प्रदर्श के प्रयोजन का काम करेगा।

**96. परिवहन या पात्र नष्ट करने या उसके हिस्से को अलग करने की समाहर्ता की शक्ति।** — जहाँ कोई परिवहन या पात्र नियम 92 के अधीन अधिहृत किया गया हो, तो जिला समाहर्ता ऐसे परिवहन या पात्र को नष्ट किये जाने या उसके हिस्से को अलग किये जाने का आदेश दे सकेगा ताकि इसे किसी उपयोग के लिए न रहने दिया जाय।

**97. अधिहरण एवं नष्ट करने के आदेश का अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप न होना।** — नियम 91 और 92 के अधीन किसी अधिहरण का आदेश किसी अन्य दंड के अधिरोपण को नहीं रोकेगा जिसका उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस नियमावली के अधीन, दंड का दायी है।

**98. सामान्य।** — (1) इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समाहर्ता किसी जप्त लघु खनिज के किसी बंदोबस्तधारी या अनुज्ञप्तिधारी को उक्त जप्त लघु खनिज को निगम के स्थानीय भण्डागार में, उन दरों पर जो निगम विनिश्चित करें, जमा करने हेतु निदेश दे सकेगा। यदि बंदोबस्तधारी या अनुज्ञप्तिधारी अथवा फुटकर अनुज्ञप्तिधारी समाहर्ता के आदेश का क्रियान्वयन करने में असफल रहता है तो समाहर्ता निगम के पास लघु खनिजों को जमा करवायेगा और उक्त बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी से खर्च वसूल करेगा।

(2) समाहर्ता, किसी लघु खनिज जप्त करने के पश्चात् ऐसे सरकारी विभागों को उनकी अनुसूचित दरों पर विक्रय करवा सकेगा ताकि सरकारी योजनाओं और स्किमों को किसी लघु खनिज की अनुपलब्धता के कारण दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

(3) इस अध्याय में सभी नीलामी ई—नीलामी के ढंग के माध्यम से संचालित अथवा नहीं भी संचालित की जा सकेगी और समाहर्ता उसका निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।

(4) यदि समाहर्ता को यह समाधान हो जाये तो ऐसी नीलामी में प्राप्त एकल बोली को अनुमोदित कर सकेगा।

### अध्याय XIII

#### अपराधों का पता लगाना, अन्वेषण और विचारण

- 99. प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने और जब्त करने की शक्ति।** — (1) निम्नलिखित में से कोई पदाधिकारी यथा—  
 (क) खान आयुक्त; निदेशक, खान या  
 (ख) समाहर्ता; या  
 (ग) समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत कोई प्रखंड अंचल स्तरीय पदाधिकारी और उसके ऊपर का जिला का पदाधिकारी; या  
 (घ) कोई खनन पदाधिकारी; या  
 (ङ.) कोई पुलिस पदाधिकारी जो सहायक निरीक्षक के पद से अन्यून स्तर का हो;  
 वारंट के बिना, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यथाविहित किये जाने वाले ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, किसी भी समय, दिन या रात, किसी भी स्थान पर प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी, और कोई दस्तावेज, नमूना, उपकरण, सवारी, पशु, वस्तु, लघु खनिज, सामग्री, कच्ची सामग्री या संबंधित कोई अन्य चीज जब्त कर सकेगा।  
 (2) ऊपर उपधारा (1) में उल्लिखित पदाधिकारी को प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने और ऐसी जब्ती करने, जो आवश्यक हो, के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तिव्यक्त बल का प्रयोग करने के लिए पूर्णतः सशक्त किया जाएगा।
- 100. किसी वाहक, परिवहन या पात्र को रोकने और उसकी जाँच करने की शक्ति।** — (1) कोई भी खनन पदाधिकारी या सहायक निरीक्षक से अन्यून स्तर का पुलिस पदाधिकारी अन्तर्वस्तुओं के सत्यापन के लिए किसी वाहक, वाहन या परिवहन या पात्र को उसकी जाँच करने के लिए रोक सकेगा।  
 (2) ऐसा पदाधिकारी उस वाहक, वाहन, पात्र और परिवहन के चालक से ऐसे वाहक, वाहन या पात्र या परिवहन को सबसे नजदीक की तुलाचौकी तक ले जाने और ऐसे वाहन, वाहक, पात्र, परिवहन के चालक या स्वामी के खर्च पर उस अन्तर्वस्तु को तौला लिये जाने की अपेक्षा कर सकेगा।  
 (3) यदि कोई व्यक्ति ऐसे खनन पदाधिकारी या ऐसे पुलिस पदाधिकारी की विधिसंगत समादेश का पालन करने से इंकार करता है, तो उसे इस नियमावली के नियम 75 के अधीन अभियोजित किया जायेगा।
- 101. बिना वारंट के गिरफ्तार करने या रोक रखने की शक्ति।** — (1) नियम 99 ..... में उल्लिखित कोई भी पदाधिकारी, बिना वारंट के इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अपराध करने को पाये गये या अपराध करने का प्रयास करते हुए पाये गये किसी व्यक्ति और/या किसी वाहन, पशु एवं सवारी के साधन को किसी समय, दिन या रात, गिरफ्तार कर या रोक रख सकेगा।  
 (2) इस धारा के अधीन की गयी सभी गिरफ्तारियाँ समाहर्ता को तुरत प्रतिवेदन करनी होगी।
- 102. संज्ञेय एवं गैर जमानती होने वाले अपराध।** — (1) इस नियमावली के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होंगे और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2/1974) के उपबंध लागू होंगे।  
 (2) कोई भी न्यायालय अधिनियम या इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सिवाय नियम 99 में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में शिकायत के, नहीं लेगा।
- 103. अन्वेषण करने की शक्ति।** — (1) कोई खनन पदाधिकारी या सहायक निरीक्षक से अन्यून स्तर का पुलिस पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण कर सकेगा।  
 (2) अन्वेषण अधिकारी, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने, शपथ या सत्यनिष्ठा पर उसका परीक्षण करने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने के विषयों की बावत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- 104. खनन पदाधिकारी की शक्तियाँ।** — (1) नियम 99 में उल्लिखित सभी खनन पदाधिकारी इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए अधिकारिता के अपने क्षेत्र में थाना के प्रभारी पदाधिकारी की शक्तियों का उपयोग करेगा।  
 (2) वह क्षेत्र जिसके लिए खनन पदाधिकारी धारा 99 के अधीन सशक्त है पुलिस थाना समझा जायेगा।
- 105. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की पेशी।** — इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी भी व्यक्ति को चौबीस घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।
- 106. गिरफ्तारियों, जब्तियों और तलाशियों के प्रतिवेदन।** — प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी कोई गिरफ्तारी, तलाशी या जब्ती करने पर इसका प्रतिवेदन चौबीस घंटे के अंतर्गत समाहर्ता एवं धारा 99 के अधीन सशक्त खनन पदाधिकारी को सौपेगा।
- 107. न्यायालय द्वारा विचारण।** — अधिनियम की धारा 30 ग के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ के निर्बंधनों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराधों का विचारण सत्र न्यायालयों द्वारा किया जायेगा।
- 108. विशेष न्यायालय।** — (1) अधिनियम की धारा 30 ख के अधीन प्रदत्त शक्ति के निर्बंधनों के अनुसार, राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन सभी या किसी अपराधों के विचारण के प्रयोजनों के लिए यदि जनहित में

आवश्यक समझती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिला में विशेष न्यायालय या तो नियुक्त या अभिहित कर सकेगी।

(2) विशेष न्यायालय विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली होगी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2/1974) के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश हों या रहे हों।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध के इस अधिनियम के अधीन विचारण का किसी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय न हो) में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता होगी और ऐसे अन्य मामलों के विचारण की अधिमानता में तय की जायेगी।

**109. विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया एवं शक्ति।** — (1) विशेष न्यायाधीश, विचारण के लिए उनके पास अभियुक्त को, सौंपे गये बिना, अपराधों का संज्ञान ले सकेगा और, अभियुक्त व्यक्तियों के विचारण में, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2/1974) द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाएगा;

(2) उप धारा (1) में यथा उपबंधित को छोड़कर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहाँ तक वे इस अधिनियम से असंगत न हों, किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष की कार्यवाही पर लागू होंगे, और उक्त उपबंधों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन को संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा;

(3) विशेष तौर पर तथा उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 326 तथा 475 के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, विशेष न्यायाधीश के समक्ष की कार्यवाही पर लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश दण्डाधिकारी समझा जाएगा;

(4) कोई विशेष न्यायाधीश स्वयं द्वारा दोषसिद्ध किसी व्यक्ति को, जिस अपराध में ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध हुआ है के दंड हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत कोई सजा सुना सकता है;

(5) कोई विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण के दरम्यान दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश 38) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले समस्त शक्तियों एवं कृत्यों का उपयोग कर सकेगा;

(6) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश, जहाँ तक व्यवहार्य हो, अपराध का विचारण दिन प्रतिदिन आधार पर करेगा।

**110. मामलों को नियमित न्यायालयों में अंतरित करने की शक्ति।** — जहाँ इस नियमावली के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात कोई विशेष न्यायालय यह समझता है कि इस अपराध का विचारण इस न्यायालय में करने योग्य नहीं है, तो वह इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के पास नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अधीन क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के पास मामला अंतरित कर सकेगा और जिस न्यायालय के पास मामला अंतरित किया गया है वह अपराध के विचारण को इस प्रकार आगे बढ़ाएगा मानो इस अपराध का संज्ञान उसी ने लिया हो।

**111. विनिर्माता, स्वामी, अधिभोगी आदि को पक्षकार बनाने की विशेष न्यायालय की शक्ति।** — जहाँ इस नियमावली के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान किसी समय यह आरोप लगता है कि इस अपराध को एक ऐसे व्यक्ति ने किसी खनिज के बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्माता, परिवाहक किसी परिसर का मालिक या अधिभोगी न होते हुये अपराध में अंतर्गस्त है तो यदि विशेष न्यायालय का उसके समक्ष प्रस्तुत प्रमाण से, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विनिर्माता, वितरक, डीलर, मालिक या अधिभोगी का भी उस अपराध से संबंध है, तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 319 की उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हो, न्यायालय उसके विरुद्ध इस अध्याय की किसी धारा के अधीन कार्यवाही करेगा।

**112. विशेष/अपर लोक अभियोजक।** — (1) इस अधिनियम की धारा 30 ग के अधीन स्थापित प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के अधिनियम 2) की धारा 24 के अधीन अधिकथित प्रक्रियानुसार किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक और एक से अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपर्युक्त धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक जिला के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्मित सूची से सत्र न्यायाधीश के परामर्श से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगा।

(3) धारा (2) अंतर्गत नियुक्त विशेष/अपर लोक अभियोजक को जिला दण्डाधिकारी के प्रतिवेदन पर हटाया जा सकेगा।

**113. अपील।** — कोई भी व्यक्ति, जो विशेष न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित है तो वह आदेश की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

**114. अभियोजन आरंभ करने की प्रक्रिया।** — (1) इस नियमावली के किन्ही उपबंधों के उल्लंघन का जैसे ही पता चले, खनन पदाधिकारी या पुलिस अवर निरीक्षक और उससे ऊपर की पंक्ति का पुलिस पदाधिकारी इस अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन मामला दर्ज करेगा।

(2) खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी तत्पश्चात मामले के अन्वेषण के लिए आगे बढ़ेगा।

(3) मामले के अन्वेषणोपरान्त मामला दर्ज होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर वह एक प्रतिवेदन दाखिल करेगा।

(4) इस प्रकार दाखिल प्रतिवेदन धारा 173 (2) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के अधिनियम 2) की धारा 190 के प्रयोजनार्थ पुलिस प्रतिवेदन समझा जाएगा।

(5) समाहर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्वोक्त प्रतिवेदन ससमय दायर किया जाए और वह न्यायालय के समक्ष मामलों के प्रभावी अभियोजन का अनुश्रवण भी करेगा।

(6) पुलिस अधीक्षक इस अधिनियम के अधीन पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दायर मामलों की स्थिति का सघन अनुश्रवण करेगा और खान आयुक्त तथा समाहर्ता को आवधिक प्रतिवेदन जमा करेगा।

#### अध्याय XIV

##### अपील और पुनरीक्षण

**115. अपील।** — (1) इस नियमावली के अधीन खान आयुक्त या समाहर्ता से भिन्न किसी खनन पदाधिकारी द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश पारित होने के साठ दिनों के भीतर, समाहर्ता के पास अपील योग्य होंगे।

(2) समाहर्ता द्वारा सभी अंतिम आदेश, आदेश पारित होने के नब्बे दिनों के भीतर, प्रमण्डलीय आयुक्त के पास अपील योग्य होंगे।

(3) खान आयुक्त द्वारा पारित सभी अंतिम आदेश, आदेश पारित होने के नब्बे दिनों के भीतर राजस्व पर्षद के पास अपील योग्य होंगे।

(4) सभी अपील का निष्पादन अपील दायर करने की तिथि से तीन महिने के अंदर होगा।•

**116. पुनरीक्षण।** — (1) अपील में समाहर्ता द्वारा पारित सभी आदेश पुनरीक्षणार्थ खान आयुक्त के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) अपील में प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा पारित सभी आदेश पुनरीक्षणार्थ खान आयुक्त के समक्ष रखे जाएंगे।

(3) सभी पुनरीक्षण वादों का निष्पादन वाद दायर करने की तिथि से दो माह के अंदर हो जाना चाहिए।

(4) राज्य सरकार किसी पारित आदेश की शुद्धता एवं वैधता तथा ऐसी किसी कार्यवाही की नियमितता से स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन से, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे प्राप्त आवेदन पर, किसी खान पदाधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के रिकार्ड या किसी दस्तावेज, जिसमें नवीकरण या फुटकर अनुज्ञप्ति के इनकार या इस नियमावली के अधीन अनुज्ञापत्र, पास आदि की मंजूरी से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, की माँग तथा जाँच कर सकेगी और ऐसे रिकार्डों की माँग करते समय निदेश दे सकेगी कि इस प्रकार माँगे गये रिकार्ड की जाँच लंबित रहने तक आदेश प्रभावी नहीं होगा। रिकार्ड परीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार ऐसे आदेश को रद्द, उलट, परिवर्तित या संपुष्ट कर सकेगी या यदि ठीक समझे तो अन्य आदेश पारित कर सकेगी।

**117. पुनर्विलोकन।** — इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी।

#### अध्याय—XV

##### प्रवर्तन।

**118. राज्य स्तरीय खनन कार्यबल।** — (1) एक राज्य स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जाएगा : —

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
| (क)  | मुख्य सचिव                                 | — | अध्यक्ष     |
| (ख)  | विकास आयुक्त                               | — | सदस्य       |
| (ग)  | प्रधान सचिव, गृह                           | — | सदस्य       |
| (घ)  | पुलिस महानिदेशक                            | — | सदस्य       |
| (ङ.) | प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन               | — | सदस्य       |
| (च)  | प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार         | — | सदस्य       |
| (छ)  | प्रधान सचिव, उद्योग                        | — | सदस्य       |
| (ज)  | प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग              | — | सदस्य       |
| (झ)  | प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग             | — | सदस्य       |
| (ञ)  | प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग           | — | सदस्य       |
| (ट)  | प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | — | सदस्य       |
| (ठ)  | प्रधान सचिव, वाणिज्य—कर विभाग              | — | सदस्य       |
| (ड)  | अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद      | — | सदस्य       |
| (ढ)  | प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग          | — | सदस्य       |
| (ण)  | निदेशक, खान                                | — | सदस्य—सचिव। |

(2) मुख्य सचिव किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को उपस्थित होने तथा राज्य स्तरीय खनन कार्य बल की बैठक में भाग लेने और योगदान करने हेतु सहयुक्त या आमंत्रित कर सकेंगे। आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

**119. संवीक्षा समिति।** — राज्य स्तरीय खनन कार्यबल, खान एवं भूतत्व विभाग को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, इन सदस्यों के साथ, जैसा वह उचित समझे, एक संवीक्षा समिति गठित करेगा। संवीक्षा समिति राज्य स्तरीय खनन कार्यबल के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

**120. राज्य स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य।** — राज्य स्तरीय खनन कार्य बल इस नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और राज्य में लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी करेगा —

- (क) अधिनियम तथा इन नियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन का उपबंध करेगा;
- (ख) इन नियमों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक नीतियों एवं मार्गदर्शनों का निर्माण करेगा;
- (ग) ऐसी कार्रवाई का जिम्मा लेने हेतु किसी अन्य विभाग निदेश जारी करेगा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिकथित पर्यावरणीय रक्षोपत्तियों के अनुसार खनन क्रियाकलाप चलाया जा रहा है।

**121. प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल।** — (1) प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जायेगा :-

|       |  |   |             |
|-------|--|---|-------------|
| (क)   | प्रमंडलीय आयुक्त                         | — | अध्यक्ष     |
| (ख)   | सीमावर्ती प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त  | — | सह-अध्यक्ष  |
| (ग)   | प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक             | — | सदस्य       |
| (घ)   | सीमावर्ती प्रमंडलों के पुलिस महानिरीक्षक | — | सदस्य       |
| (ङ.)  | वन संरक्षक                               | — | सदस्य       |
| (च)   | प्रमंडल के सभी समाहर्ता                  | — | सदस्य       |
| (छ)   | प्रमंडल के सभी पुलिस अधीक्षक             | — | सदस्य       |
| (ज)   | प्रमंडल के सभी जिला वन अधिकारी           | — | सदस्य       |
| (झ)   | प्रमंडल के सभी खनन पदाधिकारी             | — | सदस्य       |
| (त्र) | प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव                 | — | सदस्य-सचिव। |

(2) प्रमंडलीय आयुक्त ऐसे सदस्यों को, जैसा उचित समझे, अतिरिक्त रूप से सह-युक्त कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ऐसे जिलों के समाहर्ताओं एवं पुलिस अधीक्षकों को भी जिनकी सीमाएँ प्रमंडल के साथ हैं, आमंत्रित कर सकेंगे।

(3) आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

(4) यह माह में एक बार बैठक करेगी।

**122. प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य।** — प्रमंडल स्तरीय खनन कार्यबल इन नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और प्रमंडल लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित भी करेगा:-

- (क) प्रमंडल के जिलों एवं प्रमंडल के सीमावर्ती जिलों के बीच अंतर्जिला समन्वय सुनिश्चित करेगा;
- (ख) प्रमंडल के भीतर और बाहर के जिलों के आर-पार लघु खनिजों के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन को रोकने हेतु समन्वित कार्य-योजना तैयार करना और प्रारंभ करना।

**123. जिला स्तरीय खनन कार्यबल।** — (1) जिला स्तरीय खनन कार्यबल निम्नवत् गठित किया जायेगा:-

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
| (क)  | समाहर्ता  | — | अध्यक्ष     |
| (ख)  | पुलिस अधीक्षक   | — | सदस्य       |
| (ग)  | सभी अनुमंडलीय अधिकारी   | — | सदस्य       |
| (घ)  | सभी अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी   | — | सदस्य       |
| (ङ.) | प्रमंडलीय वन अधिकारी  | — | सदस्य       |
| (च)  | पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता | — | सदस्य       |
| (छ)  | जिला परिवहन अधिकारी   | — | सदस्य       |
| (ज)  | जिला खनन पदाधिकारी  | — | सदस्य-सचिव। |

(2) समाहर्ता जिला स्तरीय खनन कार्यालय की बैठक में उपस्थित होने और योगदान करने हेतु किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को सह-युक्त कर सकेंगे।

(3) आधे सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

(4) यह बैठक निश्चित रूप से माह में एक बार या विभाग द्वारा निदेशित पूर्व क्रम (frequency) पर होगी।

- 124. जिला स्तरीय खनन कार्यबल के कृत्य।** — जिला स्तरीय खनन कार्य बल इन नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा और जिले में लघु खनिजों के उत्खनन, व्यापार तथा उपलब्धता की संवीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित भी करेगा:—
- (क) यह सुनिश्चित करना कि खनन पट्टे की शर्तों के अनुसार सभी खनन क्रिया-कलाप किया जा रहा है;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि लघु खनिजों का कोई अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओभरलोडिंग, जमाखोरी तथा काला बाजारी नहीं किया जा रहा है;
- (ग) लघु खनिजों का सभी फुटकर कारबार इन नियमों के अनुसार किया जा रहा है;
- (घ) दूसरे विभागों को यह निदेश जारी कर सकेगा कि वे नियम एवं अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे कदम उठाये जो आवश्यक हों।
- (ङ.) यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिकथित पर्यावरणीय रक्षोपाय के अनुसार खनन क्रियाकलाप चलाया जा रहा है।

### अध्याय— XVI

#### जिला खनिज फाउण्डेशन

- 125. जिला खनिज फाउण्डेशन।** — (1) अधिनियम की धारा 9 ख के अधीन यथा उल्लिखित एक जिला खनिज फाउण्डेशन होगा।
- (2) अधिनियम की धारा 15 क के अधीन यथा अपेक्षित सभी बन्दोबस्तधारियों / अनुज्ञप्तिधारियों को जिला खनिज फाउण्डेशन, जिसमें वे खनन अथवा फुटकर प्रवर्तन कार्य की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बोली आगम का 2% अथवा अनुज्ञप्ति फीस देना पड़ेगा। यदि प्रवर्तन क्षेत्र दो जिलों में विद्यमान हो तो दो प्रतिशत देना पड़ेगा।
- (3) जिला खनिज फाउण्डेशन अधिनियम की धारा 9 ख के अधीन यथा अपेक्षित एक न्यास होगा।
- 126. न्यास और इसका गठन।** — (1) बिहार के प्रत्येक जिले में अधिनियम की धारा 9 ख की उप धारा (1) की शर्तों के अनुसार एक न्यास स्थापित किया जाएगा, जिसे उस जिले का जिला खनिज फाउण्डेशन कहा जाएगा।
- (2) न्यास एक शाश्वत निकाय होगा और उसका एक सामान्य मुद्रा होगी।
- (3) प्रत्येक फाउण्डेशन का मुख्यालय संबंधित जिला मुख्यालय में होगा।
- 127. जिला खनिज फाउण्डेशन के न्यास पर्वद की रचना।** — (1) प्रत्येक जिले के जिला खनिज फाउण्डेशन में निम्नांकित सदस्य होंगे, यथा—
- |   |   |            |
|---|---|------------|
| समाहर्ता  | — | अध्यक्ष    |
| अपर समाहर्ता  | — | सह-अध्यक्ष |
| सहायक निदेशक, खान/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक   | — | सदस्य सचिव |
| निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण   | — | सदस्य      |
| प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी   | — | सदस्य      |
| सिविल सर्जन   | — | सदस्य      |
| जिला कल्याण पदाधिकारी   | — | सदस्य      |
| जिला समन्वयक, जीविका  | — | सदस्य      |
| जिला लेखा पदाधिकारी   | — | सदस्य      |
| जिला सहकारिता पदाधिकारी   | — | सदस्य      |
| समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी  | — | सदस्य      |
| संबंधित जिले से संबंध रखनेवाले खनिज समनुदान धारकों के दो प्रतिनिधि (एक वृहत् खनिज तथा दूसरा लघु खनिज) | — | सदस्य      |
| खनन प्रभावित इलाके से समाहर्ता द्वारा नामित कोई व्यक्ति   | — | सदस्य      |

(2) अध्यक्ष न्यास की बैठकों में ऐसे अन्य पदाधिकारियों को जिन्हें वह आवश्यक समझता है आमंत्रित कर सकेगा।

(3) न्यास के लिए गणपूर्ति (कोरम) सदस्यों का पचास प्रतिशत होगा।

(4) न्यास की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार तथा आवश्यक होने पर बार-बार होगी और तदनु रूप विधि की उपयोगिता के संबंध में प्रभावी, पारदर्शी तथा जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से निर्णय लेगी। अध्यक्ष निधि की लेखा-बही के संधारण की व्यवस्था करेगा।

- 128. फाउण्डेशन के उद्देश्य।** — जिला खनिज फाउण्डेशन जिले के खनन प्रभावित इलाके तथा लोगों के हित एवं लाभ के लिए निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से कार्य करेगा—

(क) खनन प्रभावित इलाकों में विभिन्न विकास तथा कल्याण परियोजनाओं या कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए।

(ख) खनन के दौरान तथा उसके बाद खनन वाले जिले के लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक-आर्थिकी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम या कम करना।

(ग) खनन वाले इलाके के प्रभावित लोगों के लिए लंबी अवधि तक चलने वाली आजीविका सुनिश्चित करना।

(घ) वैज्ञानिक खनन को मान्यता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा एवं अन्य उपायों के साथ-साथ खनिज संरक्षण, पुनर्वास उपायों को सर्वोच्च महत्व देते हुए राज्य सरकार जो प्रोत्साहन योजना बनाएगी उसके क्रियान्वयन पर होनेवाले खर्च का वित्त-पोषण।

(ड.) प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना।

(च) कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन क्षेत्र के संपूर्ण हित में संपोषित करना उचित समझे।

**129. फाउण्डेशन की शक्तियाँ और कृत्य।** — फाउण्डेशन का न्यास के प्रबंधन तथा कामकाज पर संपूर्ण नियंत्रण रहेगा और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शकों या दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन इसे निम्नांकित शक्तियाँ होगी—

(क) न्यास के वार्षिक बजट तथा कार्य योजना का अनुमोदन करना

(ख) मास्टर योजना या संदर्श योजना का अनुमोदन करना

(ग) प्राथमिक क्षेत्रों तथा आवंटनों को निश्चित करना

(घ) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा वार्षिक प्रतिवेदनों का अनुमोदन करना

(ड.) न्यास के कामकाज का अनुश्रवण करना

(च) समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित गतिविधियों को क्रियान्वित करना।

**130. न्यास निधि न्यास की निधि में शामिल होगा।** — (क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर खनिज समनुदान धारकों द्वारा न्यास को किया गया भुगतान।

(ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथा अपेक्षित किसी बन्दोबस्तधारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यास को किया गया भुगतान।

(ग) बैंक खातों में किये गये जमा पर मिलनेवाले व्याज सहित सभी प्राप्तियाँ एवं आय।

(घ) किसी व्यक्ति या संगठन से न्यास द्वारा प्राप्त किया गया स्वेच्छा सहयोग, यदि कोई हो।

(ड.) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित कोई अन्य अनुदान, आर्थिक सहायता और/वित्तीय मदद।

**131. बैंक खाता।** — निधि जिला खनिज फाउण्डेशन या इस संबंध में सरकार द्वारा यथा विनिश्चित नाम से किसी अनुसूचित बैंक या इस प्रयोजन से सरकार द्वारा निर्मित किसी बैंक में बचत बैंक खाता के माध्यम से रखा जाएगा और ऐसा खाता तीन हस्ताक्षरकर्ताओं अर्थात् अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव में से कम से कम दो हस्ताक्षरकर्ताओं के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन संचालित होगा।

**132. खनिज पट्टाधारकों अथवा बंदोबस्तधारियों/अनुज्ञापितधारियों द्वारा न्यास को भुगतये राशि।** — (1) लघु खनिजों के संबंध में, दो प्रतिशत अथवा ईट-मिट्टी/अनुज्ञापत्रधारक द्वारा भुगतये स्वामिस्व/विद्यमान खनन पट्टाधारक द्वारा संदत्त स्वामिस्व की दशा में नियत कोटि के अनुसार, वार्षिक बोली/बंदोबस्ती राशि/प्रथमित स्वामिस्व के, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विहित दर से वार्षिक आधार पर खनिज समनुदान धारक से अधिभार लिया जायेगा और ऐसी समुदान के बारे में सरकार को भुगतये राशि के अतिरिक्त फाउण्डेशन के पास जमा की जायेगी।

(2) उक्त अंशदान खनिज अनुदान धारक द्वारा पूरी समुदान अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रेषित कर दिया जायेगा।

बालू बंदोबस्ती की दशा में, उक्त राशि खनन स्वामिस्व के किस्तों के साथ संदत्त की जायेगी।

(3) विहित तारीख तक भुगतान नहीं करने पर खनिज समनुदान धारक से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्णीत दर से फीस लिया जाएगा।

**133. अंशदान भुगतान का ढंग।** — सभी भुगतान जिले (जिले का नाम) में भुगतये डी.एम.एफ. न्यास, (जिले का नाम) के पक्ष में आहरण योग्य बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाएँगे।

**134. जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का व्यय/उपयोगिता।** — (1) जिला खनिज फाउण्डेशन के अधीन प्रोद्भूत निधि का व्यय/उपयोग प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) के अनुसार जिसका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है और/या उस रीति से किया जाएगा जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित करे।

(2) जिला खनिज फाउण्डेशन प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) तथा/या केन्द्र/राज्य सरकार की कोई अन्य योजना, जो लागू हो, से संबंधित जारी सभी मार्गदर्शनों तथा निदेशों का पालन करेगा।

**135. लेखा संधारण और लेखा परीक्षा।** — (1) जिला खनिज फाउण्डेशन के लेखा का संधारण सरकार द्वारा विनिश्चित स्वरूप, ढंग एवं रीति से किया जाएगा।

(2) जिला खनिज फाउण्डेशन के लेखा की लेखा परीक्षा अंकेक्षण सरकार द्वारा विनिश्चित रीति से की जाएगी।

- (3) लेखा परीक्षा के पश्चात् जिला खनिज फाउण्डेशन सरकार के पास वार्षिक प्रतिवेदन जमा करेगा।
- 136. वार्षिक प्रतिवेदन।** — (1) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, फाउण्डेशन संबंधित वर्ष के लिए न्यास की गतिविधियों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाएगा।  
(2) वार्षिक प्रतिवेदन फाउण्डेशन द्वारा इसके अनुमोदित किये जाने की तारीख से एक महीने के भीतर सरकार के पास जमा किया जाएगा और फाउण्डेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।  
(3) प्रत्येक फाउण्डेशन का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
- 137. फाउण्डेशन को देय राशि का अनुश्रवण।** — प्रत्येक बन्दोबस्तधारी/खनिज समनुदान धारी फाउण्डेशन को भुगतये राशि का परिहार सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट बैंक खाते में करेगा। रॉयल्टी वसूलने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक पदाधिकारी प्रत्येक बन्दोबस्तधारी/खनिज समनुदान धारी द्वारा देय तथा संदत्त राशि की पंजी का संधारण करेगा और प्रत्येक माह के अंत में फाउण्डेशन के अध्यक्ष के पास उसका समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 138. प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों की पहचान :**
- (1) प्रभावित क्षेत्र : —**  
(क) प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र वे हैं जहाँ उत्खनन, खनन, विस्फोट, परिष्करण एवं कचरा निस्तारण, अत्यधिक कचरे का ढेर, अवशिष्ट ताल, परिवहन गलियारे आदि जैसे सीधे खनन से संबंधित कार्य स्थित हों और जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
- गाँव और ग्राम पंचायतें जहाँ खान स्थित हैं तथा जिनमें काम चल रहा हो। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोस के गाँव, प्रखण्ड या जिले या यहाँ तक की पड़ोसी राज्य तक विस्तारित हो सकते हैं।
  - किसी खदान या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट खदानों के समूह, भले ही संबंधित जिले या सन्निकट जिले के अन्तर्गत हो, की त्रिज्या के भीतर का कोई इलाका।
  - वैसे गाँव जहाँ खदानों से विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बसाया या पुनर्वासित किया गया हो।
  - वैसे गाँव जो साभिप्राय अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए खनन क्षेत्र पर निर्भर हों और परंपरा से उनका, उदाहरण के लिए गोचारण, छोटे-छोटे वन्य उत्पादों के संग्रह आदि के लिए परियोजना क्षेत्र पर अधिकार बनता हो।
- (ख) अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ कि स्थानीय जनता खनन से संबंधित कार्यों के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिणामों के कारणवश प्रतिकूलतः प्रभावित हैं। खनन का बड़ा नकारात्मक प्रभाव जल, भूमि और वायु की गुणवत्ता में गिरावट के माध्यम से नदी के प्रवाह में कभी, भूजल का रिक्तीकरण, खनन कार्य से जल जमाव तथा प्रदूषण, खनिजों का परिवहन, वर्तमान आधारभूत संरचना तथा संसाधनों पर बढ़ा हुआ बोझ हो सकता है।
- (2) प्रभावित लोग : —**  
(क) निम्नांकित प्रत्यक्ष प्रभावित लोग समझे जाएंगे—
- भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3(ग) के अधीन, यथा परिभाषित “प्रभावित परिवार”।
  - भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3(ट) के अधीन यथा परिभाषित “विस्थापित परिवार”।
  - संबंधित ग्राम सभा द्वारा यथा उपयुक्त पहचान की गयी कोई अन्य।
- (ख) खनन द्वारा प्रभावित लोगों में वे लोग शामिल होंगे जिनका खनन की गयी भूमि पर वैधानिक एवं व्यवसायिक अधिकार है, तथा वे लोग भी जिन्हें भोगाधिकार तथा पारंपरिक अधिकार हैं।
- (ग) जहाँ तक संभव हो, प्रभावित परिवारों की पहचान यथास्थिति ग्राम सभा या शहरी स्थानीय निकाय के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से की जाएगी।
- (3)** जिला खनिज फाउण्डेशन ऐसे प्रभावित इलाकों तथा लोगों की अद्यतन सूची तैयार तथा संधारित करेगा।

## अध्याय XVII

### छूट

- 139.** इस नियमावली के उपबंधों से लघु खनिजों को छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति। — राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा या तो पूरे राज्य में या राज्य के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी विनिर्दिष्ट अवधि या



अवसर के लिए या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, किसी लघु खनिज को पूर्णतः या अंशतः और वैसे शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन, जिसे विहित करना उचित समझे इस नियमावली के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी।

**140. इस नियमावली के किसी उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल करने की सरकार की शक्ति।** — (1) राज्य सरकार इस नियमावली के एक या अनेक उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगी यदि सरकार के विचार से ऐसी शिथिलता लोक हित में आवश्यक हो।

(2) इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, राज्य सरकार ऐसे मामले में, जिसमें सरकार लोक हित में उचित समझती है तो, खनन पट्टा/खनन बंदोबस्ती की मंजूरी दे सकेगी, और लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, इस नियमावली में विहित शर्तों एवं निबंधनों से भिन्न शर्तों एवं निबंधनों पर किसी को उत्खनन अनुज्ञापत्र / संचलन अनुज्ञापत्र की मंजूरी को प्राधिकृत कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार इस नियमावली में विहित शर्तों एवं निबंधनों से भिन्न शर्तों एवं निबंधनों पर किसी सरकारी विभाग अथवा राज्य स्वामित्व वाले निगम को अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किसी इलाके में खनन पट्टा/बंदोबस्ती/फुटकर अनुज्ञप्ति की मंजूरी दे सकेगी।

**141. किसी कार्य विभाग को खनन पट्टा आदि।** — (1) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी कार्य विभाग को, जिलों के विनिर्दिष्ट संख्या में किसी विशिष्ट योजना के लिये विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये अनुज्ञप्ति/पट्टा मंजूर कर सकेगी।

(2) उक्त कार्य विभाग को बकाया स्वामित्व/मालिकाना फीस तथा ऐसी अन्य फीस, जो इस नियमावली के अधीन लागू हो, देनी होगी

## अध्याय XVIII

### प्रकीर्ण

**142. खनन पर सामान्य प्रतिबंध पर रोक।** — बिना राज्य सरकार से परामर्श के कोई प्राधिकार या अभिकरण या संस्थान या कोई सक्षम व्यक्ति लघु खनिज के खनन पर सामान्य पूर्ण प्रतिबंध निर्गत नहीं करेगा। यदि राज्य सरकार को ऐसे प्रतिबंध लगाये जाने की जानकारी होती है तो वह उक्त प्रतिबंध को लोकहित में रद्द करने में सक्षम होगी।

**143. पदाधिकारियों का लोक सेवक होना।** — (1) अधिनियम अथवा इस नियमावली के अधीन किसी शक्ति का उपयोग करने या किन्हीं कार्यों को करने में सक्षम सभी पदाधिकारी और व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 21 अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

(2) इस अधिनियम या इस नियमावली या खनन राजस्व से संबंधित तात्कालिक रूप से लागू किसी अन्य कानून के अनुपालन में सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य या करने हेतु दिये गये आदेश के लिए राज्य सरकार या किसी खनन पदाधिकारी के विरुद्ध क्षति के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं होगी।

(3) इस नियमावली के अनुसरण में कुछ करने या किये जाने के आरोप के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी वाद पर कोई सिविल न्यायालय विचारण नहीं करेगा, और पूर्व अनुशास्ति को छोड़कर, कोई दण्डाधिकारी किसी खनन पदाधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या इस नियमावली के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये किसी आरोप का संज्ञान नहीं लेगा।

**144. आदेशों का लागू रहना।** — (1) बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972, (समय-समय पर यथा संशोधित) बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण) नियमावली, 2003, बालू नीति, 2013, या खान आयुक्त, समाहर्ता, राजस्व पर्षद या खनन के मामलों से संबंधित उन नियमावलियों और जो उनकी समाप्ति के तत्काल पूर्व लागू थीं के अधीन नियुक्त किसी अन्य खनन पदाधिकारी के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश अधिसूचना, नियम या विनियम, जहाँ तक ऐसे आदेश या अधिसूचना या नियम या विनियम इस अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हों, अविराम लागू और इस अधिनियम तथा इस नियमावली के अधीन निर्मित समझे जाएंगे।

**145. निरसन और व्यावृत्तियाँ।** — (1) एतद् द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 और बालू नीति, 2013 निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली तथा नीति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम तथा इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझा जाएगा।

(3) ऐसे निरसित नियमावली के किन्हीं उपबंधों के सभी संदर्भ इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के संदर्भों के रूप में समझे जाएंगे।

(4) इस नियमावली के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व किसी पदाधिकारी, प्राधिकार या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियाँ (अन्वेषण के माध्यम से की गयी कार्यवाहियों सहित) ऐसे प्रारंभ पर इस नियमावली के अनुसार इसके समक्ष लंबित कार्यवाही समझी जाएंगी और तदनु रूप कार्रवाई की जाती रहेगी।

146. कठिनाई दूर करने की शक्ति। — इस नियमावली के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा उपबंध कर सकेगी जिसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।
147. नियमावली का रखा जाना। — (1) यह नियमावली जैसे ही बनाई जाय, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।  
(2) इस नियम के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, इसके निर्गत होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

*The 10<sup>th</sup> October 2017*

**No. 3018/M**—In exercise of the powers conferred under Section 15 read with Section 23C and Section 26 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules:-

### **BIHAR MINOR MINERAL RULES, 2017**

#### **CHAPTER I**

#### **PRELIMINARY**

1. **Short Title, Extent and Commencement,-**
  - (1) These rules may be called the **BIHAR MINOR MINERAL RULES, 2017**.
  - (2) *It shall extend to the whole State of Bihar.*
  - (3) It shall come into force on the day of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions-** (1) In these Rules, unless otherwise required in the context—
  - (i) **“Act”** means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957);
  - (ii) **“Collector”** means Collector-cum-District Magistrate of a district or any person appointed by the Government to exercise the powers and perform the functions of the Collector-cum-District Magistrate;
  - (iii) **“Competent Officer”** means -
    - (a) in the case of grant of quarrying permits in land notified as reserved and protected forest under the Indian Forest Act, 1927 (Central Act XVI of 1927), where the actual mining operation involved is merely removal from the surface or from a depth not exceeding five feet and to a limit of 10,000 cubic feet only, Divisional Forest Officer of the reserved and protected areas concerned, and;
    - (b) in all other cases in respect of all lands, and sub-soil including any right in mines and minerals whether discovered and whether being worked or not, the Mining Officer of the District;
  - (iv) **“Corporation”** means Bihar State Mining Corporation;
  - (v) **“Department”** means the Department of Mines and Geology, Government of Bihar;
  - (vi) **“Divisional Commissioner”** means the Commissioner of a Division appointed as such by the State Government;

- (vii) **“Director of Mines”** means the Director of Mines appointed as such by the State Government;
- (viii) **“Export”** means to take out of the State of Bihar otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government;
- (ix) **“Government”** means the State Government of Bihar;
- (x) **“Import”** means to bring into the State of Bihar otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government;
- (xi) **“Local Authority”** means a Municipal Committee, District Board or other authority legally entitled to, or entrusted, by the Government with the control or management of a municipal or local fund;
- (xii) **“Licensing Authority”** means an officer who is authorized to grant, suspend and cancel a mining lease, retail license, movement permit or any other license etc under the Act & these rules;
- (xiii) **“Mines Commissioner”** means the Commissioner of Mines and Geology, Bihar, or any other Officer authorized in this behalf by the State Government to perform the duties of Commissioner under these rules;
- (xiv) **“Minor Minerals”** means minor minerals as defined in clause (e) of Section 3 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and
  - (a) includes such minor minerals like sand, morram, chips, stones, boulder, bricks, brick earth, ordinary earth used for land filling, बजरी/बोल्डर found in the river bed, decorative stone, China clay, quartz, marble, sand stone, silica sand, etc; and
  - (b) includes such minor minerals as notified by the Ministry of Mines in their Notification No. SO 423 dated 10.02.2015;
- (xv) **“Mineral Disposal Permit”** means a permit given for disposal of -
  - (a) minor minerals/silt/flyash/jhama/raabish or any by-product excavated or generated during the process of maintenance/drainage of any drain or canal or river;
  - (b) minor minerals/silt/flyash/jhama/raabish or any by-product excavated or generated during the process of construction or repair or demolition of any building or structure;
  - (c) minor minerals/silt/flyash/jhama/raabish or any by-product excavated or generated or accumulated due to floods or dispersed through any production activity;

**Note:** - A person having a Mineral Disposal Permit need not require a Movement Permit, as defined in Rule 2(1)(xx) to transport the above minerals from one place to another.

- (xvi) **“Mining Lease”** means a mining lease or settlement in respect of minor minerals and includes quarrying permits and any other mineral concession, permitting the mining of minor mineral(s) in accordance with the provisions of these rules;
- (xvii) **“Mining Plan”** means a plan prepared by a Recognized Qualified Person (RQP) on behalf of Settlee of minor minerals and includes progressive and final mine closure plans;
- (xviii) **“Mining Officer”** means the officer as mentioned under Rule 5 of these rules;
- (xix) **“Mining Revenue”** means revenue derived or derivable from any royalty, fee, tax, payment (other than a fine imposed by a Criminal Court) or confiscation imposed or ordered under these rules or any other law for the time being in force relating to minerals;
- (xx) **“Movement Permit”** means an authorization granted under these rules for movement of any minor mineral from one place to another;
- (xxi) **“Place”** includes building, house, shop, boat, booth, vessel, raft, vehicle, conveyance or tent enclosure;
- (xxii) **“Public Place”** means any place to which public has access whether as a matter of right or not and includes all places visited by public and also includes any open space;
- (xxiii) **“Police Station”** means a police station as defined under clause (s) of Section 2 of the Code of the Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974);;
- (xxiv) **“Prescribed”** means prescribed by these rules or guidelines;
- (xxv) **“Public Demand”** means public demand as defined under Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Act 4 of 1914);
- (xxvi) **“Recognized Qualified Person”** means a person who has been notified as such by the Department under the Rule 20;
- (xxvii) **“Retail License”** means a retail license granted under these rules for carrying on any retail activity of minor minerals and includes any brick production activity;
- (xxviii) **“Sandghat”** means a sand bearing area from where sand may be extracted and transported by means of a carrier;
- (xxix) **“Settlee”** means a person (as defined in these rules) holding a valid settlement/lease for quarrying/raising sand and other minor minerals from the settled/ lease hold area and would also include the plural there of;
- (xxx) **“Settlement”** means a mining right given on behalf of the Government to quarry, win, work and carry away sand and other minor mineral(s) specified therein through a competitive bidding process as notified by the State Government;
- (xxxi) **“State Government”** means the State Government of Bihar;
- (xxxii) **“Sand Policy, 2013”** means the Sand Policy as notified by the State Government vide its notification no. 2214 dated 27.08.2013;

- (xxxiii) **“Temporary Structure”** means any structure which does not require foundation to be erected and is easy to dismantle, very easy to change the configuration of the structure;
- (xxxiv) **“Transit”** means to move from one State to another State through the State of Bihar;
- (xxxv) **“Transport”** means to remove from one place to another within the State of Bihar;
- (xxxvi) **“Warehouse”** means a place where storage of minor mineral is permitted;
- (xxxvii) **“Works Departments”**- means Departments of the State or Central Government who are engaged in executing public projects like roads, rail, buildings, dams, water supply etc.

(2) Words and expressions used but not defined in these Rules shall have the same meaning which are assigned to them in the Act.

## CHAPTER II ESTABLISHMENT AND CONTROL.

3. **Appointment of Mines Commissioner** - The State Government may, by notification, appoint a Mines Commissioner who shall be responsible for Administration of these rules at the State level.
4. **Appointment of Director Mines.** - The State Government may, by notification, appoint a Director Mines who shall be responsible for Administration of these Rules in the field offices at the district level.
5. **Mining Officer.** - (1) The Mines Commissioner, Director Mines, Additional Director, Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, District Mining Officer, Mineral Development Officer and Mining Inspectors shall be the Mining Officer for the purpose of these rules.  
(2) The Collector or any other Officer authorized by him within his district shall also be competent to exercise the powers of the Mining Officer for the purpose of these rules.
6. **Delegation and Withdrawal of Powers.** - (1) The State Government may delegate its powers to the Mines Commissioner or Collector subject to such limitations and conditions as may be specified in the order of delegation.  
(2) The State Government may, by an order, also withdraw from any Officer or person any or all the powers so delegated.
7. **Role of the Collector.** - (1) The Collector of the district shall be responsible for the complete implementation of the provisions of the Act and these rules;  
(2) The Collector shall also be competent to exercise the powers of the Mining Officer under these rules;  
(3) The Collector shall exercise direct control and superintendence over all the Mining Officers of the district.  
(4) The State Government may, by notification, confer the powers of the Collector to any Officer, not below the rank of Inspector of the

Mines Department or any Officer, not below the rank of Deputy Collector, of the Revenue Department, with such designations, powers and duties as the State Government may think fit.

**8. Role of the Superintendent of Police.** – The Superintendent of Police shall :-

- (a) assist the Collector in ensuring implementation of the provision of the Act and these rules;
- (b) work under direct control and superintendence of the Collector;
- (c) enforce and implement such lawful directions of the Collector or Mines Commissioner or Director Mines as issued under the Act and these rules;
- (d) submit such reports and in such manner as the Collector or the Mines Commissioner or Director Mines may desire.

**9. Powers and functions of the Mines Commissioner.** - The Mines Commissioner –

- (a) shall exercise over all control and superintendence over all Mining Officers in the State;
- (b) may require any Settlee, or any other licensee etc by notice to produce or caused to be produced before him such documents, accounts or other evidence which may be deemed fit;
- (c) may suo motto call for and examine the record of any proceeding conducted by any authority, officer or person subordinate to him under the Act and these rules and if he considers that any order passed therein is erroneous or is prejudicial to the interest of revenue, mining rules and environmental conditions, pass such order as he deems fit after giving the Settlee or the person concerned an opportunity of being heard;
- (d) shall monitor the activities of the Settlees or other licensees etc and if he is prima facie satisfied that any Settlee or other licensee etc has violated all or any of the condition of the lease/Retail license or is not complying to any lawful direction issued by any authority, he shall direct the Collector to initiate proceeding cancel/suspend such lease or such license.

Provided further that the Collector shall conduct a detailed inquiry against the said violation and then proceed to issue a notice to the said Settlee/licensee as per Rule 56.

**10. Power and function of Director Mines.** – (1) He shall head the Directorate of Mines and shall exercise Administrative Control over all Mining Officers of the Department.

(2) He shall be responsible for the security of all mining operations in the State. He shall also be responsible for ensuring that the interest of the State are protected and all the Settlees, Corporation, other licensees, operate as per the provisions of the Act and these rules.

(3) He shall be responsible for the collection of royalty and other revenues payable.

(4) There shall be a Directorate of Security under him which shall employ adequate personnel on either deputation or recruitment from Civil / Police Personnel or retired Defense/Para Military/ Police Personnel.

(5) The Directorate of Security shall function under the control and supervision of Director and shall discharge such duties as may be assigned to it by the Director including the investigation of the offences under Chapter XI of these rules.

(6) The structure of the Directorate of Security shall be approved by the State Government.

**11. Mining Offices at the District Level.** – (1) All districts of the State shall have a Mining Office headed by an appropriate Mining Officer to be appointed by the State Government.

(2) All Mining Officers heading a District Mining Office shall exercise all financial powers including that of a Drawing-cum-Disbursing Officer.

**12. Persons with Special Powers.** – The State Government may, by notification, and in order to implement the Act and these rules, empower any Government functionary not being a Mining Officer, with powers to perform all or any of the functions of any Mining Officer under these rules, and such person shall, in exercise of these functions, be deemed to be a Mining Officer.

### CHAPTER – III

#### GENERAL CONDITIONS OF MINING LEASE FOR MINOR MINERALS.

**13. Restriction of Mining of Minor Minerals.** – No person shall excavate, produce, manufacture, distribute, transport, collect, store, possess, purchase, sell any minor mineral except under a valid mining lease or a license or movement permit, as the case may be;

Provided that the State Government may, by notification, allow any State Owned Company to undertake such activities as it may specify.

**14. Mining to be on Lease Basis.** - All mining of minerals shall be done on mining lease basis. A person or firm undertaking mining or excavating or producing minor minerals shall be called a Settlee/licensee. No Settlee/Licensee can claim to be an owner of the land, nor of the minerals that he will be excavating.

**15. Mining Area or Mining Plot.** – No mining area shall ordinarily be less than 5 hectares. Each such area shall be called a 'Mining Plot'.

Provided that the State Government may decide to have a Mining Plot of less than 5 hectares or more than 5 hectares in terms of the Notification No. SO141E dated 15.01.2016 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and their guidelines as issued from time to time.

**16. Mining Cluster.** – The State Government may designate a group of mining plots into clusters in terms of the above mentioned notification of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and their guidelines as issued from time to time.

- 17. Mining Depth.** - In case of sand ghats, the depth of mining shall not be more than 3 meters or the water level, whichever is less.
- 18. Duration of Mining Lease.** - Ordinarily, the duration of the Mining lease for minor minerals shall be 5 years.

Provided that the State Government may decide to settle a particular mining lease for a particular minor minerals for a period of 3 years or less depending upon each case.

- 19. Mining Plan.** - The Mining plan shall be prepared for each mining plot or mining cluster. Each Settlee/Licensee shall have to submit a Mining Plan, to the Collector before commencing the mining operation. Such mining plan shall be prepared by any Recognized Qualified Person. The Department shall lay down detailed procedures for preparation of approval of a Mining plan.
- 20. Recognized Qualified Person.** - (1) A Recognized Qualified Person is a person who is Graduate in Engineering, preferably in Mining Technology, Geology or related areas with at least three years of work experience in Mining/Construction/Architecture sector.  
(2) The Department shall prepare a panel of Recognized Qualified Persons who shall prepare the mining plan on behalf of the Settlees.  
(3) The Department may relax the minimum eligibility criteria for a person to be empanelled as a Recognized Qualified Person.

- 21. Environmental Clearance.** - Each Settlee/Licensee has to obtain a valid Environmental Clearance in terms of the Notification No. 1533A dated 14.09.2006 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India.

Provided further that the Settlee/Licensee shall obey and comply with such other instructions regarding environmental protection and Environmental Clearance issued from time to time by the Government of India, State Government, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board and the Collector of the District.

- 22. Mineral Development Fund.** - All Settlees/Licensees or such other person or entity as directed by the State Government, shall deposit two percent of the mining lease amount every year in the Mineral Development Fund to be operated by the Mineral Development Foundation as indicated in Chapter XVI of these rules.

Provided further that the State Government may by notification increase or decrease the percentage of this contribution.

- 23. Manual Labor on Sandghats.** - (1) In case of sand ghats, no machines or equipments like poclain, loaders, excavators etc will normally be allowed for the purpose of excavation. Excavation of sand from sand ghats should be done preferably using manual labor.

Provided that the Department or the Collector may allow the use of above mentioned machines in certain or all ghats in cases of any emergency or shortage of labor.



- (2) The Department may lay down further guidelines for the purpose of protecting the sand ghats and their ecology from environmental prospective.
- 24. General Restricted Areas for Mining on Sand Ghats.** – (1) No mining should be allowed up to 300 meters from a railway bridge or a road bridge.  
 (2) No mining should be allowed up to 50 meters from any cremation ground/religious place.  
 (3) No mining should be allowed within 5 meters from the water line of either side of river.  
 (4) In addition to the above, the Collector may specify additional restricted areas for each mining lease in the mining plan itself.
- 25. Restriction on number and Area of Mining Lease.** – No person or firm shall be allowed to hold a Mining Lease for more than 100 hectares.  
 Provided further that the Department may allow more than 100 hectares to a person or firm in an area if it is found that the said mining area is not generating enough interest amongst the prospective bidders.
- 26. Mining in the Forest Areas.** – (1) The minor minerals lying inside any forest area may be bid out by the Collector with the condition that the prospective Settlee brings the due permission from the Forest Department under the Forest Conservation Act, 1980.  
 (2) The formal mining lease deed shall be executed only after the required clearance from the Forest Department is received.
- 27. Mining on the Raiyati Land.** – (1) Wherever any minor mineral is discovered or available on a raiyati land, the Collector shall be competent to bid out the said minor mineral as per the procedure laid down in these rules.  
 (2) The Collector may enter into such Agreement with the Raiyat and pay such compensation as may be mutually agreed.  
 (3) Such Raiyat shall not *ipso facto* get a right for excavating the mineral and shall have to participate in the public bidding.
- 28. Special Licenses for Excavation of Ordinary Earth.** – (1) There shall be special licenses given for Mining/Excavation of Ordinary Earth in the district.  
 (2) The Department shall lay down detailed guidelines for such licenses and Mining/Excavation and trade in Ordinary Earth.
- 29. Special Licenses for Brick Kiln Owners.** – (1) Each brick kiln owner shall be required to obtain a retail license for operating the brick kiln and producing bricks from brick earth.  
 (2) The Department shall lay down detailed guidelines for such retail licenses and Mining/Excavation/Manufacture and trade in bricks and brick Earth.
- 30. Permits for Mineral Disposal.** – (1) Every person desirous of undertaking excavation as per sub Rule (xv) of Rule 2 of these Rules shall have to obtain Mineral Disposal Permit from the Collector.

- (2) The Department shall lay down detailed guidelines for such Mineral Disposal Permits.
- 31. Relationship between a Settlee and Other Licensees.** – A person cannot be a Settlee or a licensee at the same time. A Settlee cannot be given any other license under these rules and vice versa.
- 32. Licensing Authority.** – The Collector shall be the Licensing Authority for all the mining lease and any other license. He may, however, delegate issuance of movement permit, e-challan and such other functions to any Mining Officer of the District.
- 33. Other Conditions.** – (1) The Department may require any Settlee/licensee to take up environmental friendly activities and set up such modern facilities like weigh bridges, computers, offices at the mining sites or his premises.  
(2) The Department may lay down such other conditions from time to time on the Settlees/Licensees and the Corporation as it may deem fit in order to enforce the provision of the Act and these rules. These may, inter alia, include such conditions as are peculiar to a particular minor mineral or a particular geographical area.

#### CHAPTER – IV

#### BIHAR STATE MINING CORPORATION.

- 34. Activities by the Bihar State Mining Corporation.** – (1) The State Government may entrust all or any of the mining activity or trade to Bihar State Mining Corporation. The Corporation may undertake, in particular, mining activity, wholesale trading, retail trading, storage, transportation etc of minor minerals.  
Provided that if the Corporation wishes to undertake mining or excavation of minor minerals, it shall participate in the open public bidding as required under these rules.  
(2) The Corporation may enter into an arrangement with any Government or semi Government or private undertaking for the said purpose.
- 35. Corporation to buy minerals at prescribed rates.** – The Department may direct all the new Settlees or existing Settlees or any other licensee to sell all or any proportion of their produce to the Corporation at such rates as may be prescribed.
- 36. Prescribed rates for new Settlees/Licensees.** – All new Settlees/licensees shall be required to supply the Corporation the minor minerals excavated by them at a rate arrived at through competitive bidding.
- 37. Prescribed rates for existing Settlees/Licensees.** – (1) While fixing the prescribed rates for existing Settlees/licensees, the Department may seek report from the Mining Officer of the District and after considering the cost of production, handling charges, transport cost and any other cost, fix the proposed prescribed rate.  
(2) On this proposed prescribed rate, the Department may seek an objection from the existing Settlees/licensees and after hearing the said Settlees/licensees, the Department may finalize the prescribed rate.

**(Explanation** – For the purpose of this rule, the existing Settleses/licensees means the person or the firm who is owning a mining lease or a license on the day of promulgation of these rules.)

## **CHAPTER – V**

### **PROCEDURE FOR GRANT OF A MINING LEASE.**

- 38. E-bidding.** – (1) All mining leases for a Mining Plot or a mining cluster thereof shall be granted through a public bidding, preferably through e-bidding mode.  
(2) The Department shall issue detailed guidelines for this purpose.
- 39. Eligibility for Individuals.** – For person to be eligible for grant of a mining lease or any license, he should be,
  - (a) A citizen of India;
  - (b) PAN Card Holder;
  - (c) should not be a defaulter or blacklisted or debarred from holding a mining lease or any license or in arrears of any government dues;
  - (d) should be solvent and bear good moral character and should not have been convicted of any offence under any Act and the same should be duly supported by a police verification report;
  - (e) should not hire or employ persons who are below eighteen years of age or who have criminal background;
- 40. Eligibility for Firms.** – For a Firm to be eligible for grant of a mining lease or any license, it should be
  - (a) duly registered under the Companies Act, 2013;
  - (b) should be registered with the Income Tax Department;
  - (c) providing an affidavit that there is no criminal case or dues pending against the said firm with the same duly supported by a police verification report;
  - (d) should not be a defaulter or blacklisted or debarred from holding a mining lease or any license;
  - (e) should be solvent and should not have been convicted of any offence under any Act;
  - (f) should not hire or employ persons who are below eighteen years of age or who have criminal background.
- 41. E-Bidding Procedure.** – (1) The E-bidding shall be conducted by the Department where the interested bidders may participate. The Department may also authorize the Collector to conduct the e-bidding at the district. The Department shall be free to lay down its own procedures for such bidding.  
(2) The bidding shall be conducted by Mining Plot wise or a cluster thereof.  
(3) The Department shall lay down a minimum reserve price for each mining plot or a cluster. Any person/firm interested in the e-bidding shall have to deposit the minimum reserve price through a demand draft to the Department.  
(4) The successful bidder shall be then be registered with the Department and shall be required to submit due GST registration.

(5) Upon the submission of the GST registration, the Department shall recommend to the Collector to issue the mining lease.

(6) The Collector, as Licensing Authority, before issuing the mining lease to the successful bidder, shall see that the Successful bidder -

- (a) has deposited the required security deposit.
- (b) has deposited a bank guarantee for the bidding period in the format suggested by the Department.
- (c) has deposited the Mining Plan.
- (d) See that the successful bidder has deposited the required stamp duty & such other fee.

(7) Upon the receipt of the mining lease from the Collector, the successful bidder shall then obtain environmental clearance from the Competent Authority within 3 months.

(8) Upon obtaining the environment clearance, the successful bidder shall inform the Collector and thereafter the Collector shall authorize the District Mining Officer to enter into an Agreement with the Settlee and issue the work order for commencement of the mining operation.

(9) The Department shall lay down the draft Agreement format to be signed by the Settlee.

(10) The Department shall also be competent to issue such guidelines or clarifications to the Collector in order to conduct the E-bidding smoothly.

## **CHAPTER – VI**

### **STORAGE, TRADING, SALE AND PURCHASE OF MINOR MINERALS.**

**42. Regulation of Trade in Minor Minerals.** – (1) The business of storage, trading, sale and purchase of minor minerals shall be regulated by the State Government through a regime of lease, licenses and permits.

(2) The State Government may issue such further directions from time to time as it deems fit to regulate the trade in Minor Minerals.

**43. Wholesale Trade.** – (1) The Department may undertake the wholesale trade upon itself or may authorize the Corporation to be the Wholesale Trader of certain or all minor minerals in the State.

(2) The Settlee/licensee, who undertakes the mining operation of the minor minerals, shall be required to excavate/manufacture the minerals and deposit with the Corporation, at the prescribed rates.

(3) The Settlee/Licensee shall not be permitted to sell the minor minerals directly to any person or firm.

(4) The Corporation, as wholesale trader of minor minerals, shall be free to sell the minor minerals to retailers, Government and contractors at market rates or such rates as the State Government may direct.

**44. Buffer Stock.** – To regulate the prices of minor minerals, the Department may authorise the Corporation to maintain a certain buffer stock of some or all the minor minerals and sell the same at such places and at such prices as the Department may direct.

- 45. Retail Trade.** – (1) The Collector, in order to regulate the retail trade in minor minerals, issue retail licenses in the district to retailers who shall be authorised to store and sell the minor minerals to the public at large. (2) The retail licenses shall be issued in sufficient number in all the districts by the Collector. The Collector shall be competent to decide the number of such retailers.  
(3) In case the retailers are transporters or transport agencies, they may be required to be separately get registered with the Department.  
(4) All the retail licensees, including transporters, should be necessarily be having a GST registration.  
(5) The Department shall lay down other conditions of such retail licenses and retail businesses.
- 46. Renewal of Lease and License.** – (1) There shall be ordinarily no renewal of mining lease to a Settlee/licensee. Once the period of the mining lease is over, the Department or the Collector shall again put the said Mining Plot or the Cluster for public bidding. However, in case of any unforeseen delay in conducting a fresh bidding, the Collector may renew the Mining Lease of the earlier Settlee/licensee, till such period, not beyond six months, as the fresh bidding is completed.  
(2) In case of retail licenses, however, the Collector may renew a retail license for such period as may be indicated by the Department in their guidelines.
- 47. Sale price of Minor Minerals.** – (1) The sale price of minor minerals to the end user or the public shall be decided by the market forces.  
(2) The State Government or the Collector, however, may intervene in such manner as deemed appropriate, to regulate the market prices in public interest.
- 48. Non Transferability of Licenses.** – All Licenses issued or renewed under these rules shall be non transferable.

## CHAPTER VII

### E-REQUIREMENTS.

- 49. Usage of Electronic Procedures.** - The Mines Commissioner may, by notification, require any Mining Officer, Police Officer, Settlee/Licensee or any other Stake Holder to file their returns, statements and activities electronically and undertake all or any operations through electronic mode.
- 50. E-Challan.** – (1) The movement of all minor minerals, whether by Settlee/Licensee or by the Corporation, shall be monitored through e-Challan system to be developed by the Department.  
(2) Whoever refuses to adhere to the system of e-challan shall be prosecuted under the provision of these rules.
- 51. Mining MIS.** – (1) The Department may also require all the Settlees/Licensee, the Corporation and other persons engaged in the transport and trade of minor minerals to come under the purview of the provision of these rules and under take their activities as per the Mining MIS system to be developed by the Department.

(2) Whoever refuses to adhere to the system of Mining MIS shall be prosecuted under the provision of these rules.

(3) The Department may lay down detailed guidelines for its MIS.

#### **CHAPTER -VIII**

#### **GRANT OF MOVEMENT PERMITS FOR MOVEMENT OF MINOR MINERALS.**

**52. Movement of Minor Minerals.** -(1) No minor minerals shall be imported, exported or transported or transited within or from outside or through the State except with a valid movement permit/challan/e-challan and subject to such fee (if any) payable as may be prescribed; (2) If any consignment of minor mineral is being transported by road from a place to another such place, the driver or any other person in-charge of the vehicle shall obtain transit permission in the prescribed manner from the Competent Authority;

(3) In case the driver or person referred to in sub-section (2) fails to comply with the provisions of sub-section (2), he may, apart from being levied such penalty as the State Government may decide, be prosecuted under the provision of these rules.

**53. Restrictions on Vehicles carrying Minor Minerals.** - (1) The State Government may lay down reasonable restrictions on the vehicles transporting any minor minerals and may require them to adhere to certain specifications.

Provided further that the State Government may require the transport vehicles to install GPS devices or such other devices, as it may require and give such directions as it deems fit.

(2) The State Government may also specify the size and nature of vehicle/transport to be used for transporting any minor mineral from its source of excavation/production to the warehouse of the Corporation and to the Retail licensee.

**54. Power to Regulate Transport of minor minerals.** - (1) The State Government may, by notification, regulate the movement or import or export of any or all minor minerals into or from or through the State or any specified part or area of the State.

(2) The Department may set up Check Post, Barriers, Weigh bridges etc and such other facilities to regulate the movement of minor minerals.

**55. Non Transferability of Permits.** - All movement permits issued under these rules shall be non transferable.

#### **CHAPTER - IX**

#### **CANCELLATION OF MINING LEASE, RETAIL LICENCES OR PERMITS.**

**56. Power to Suspend or Cancel Mining Lease, Retail License or Permit.** - (1) The Collector shall be competent to cancel any mining lease of any Settlee/licensee of a retailer in his district. He shall also be competent to cancel any movement permit issued under these rules.

(2) Subject to such restrictions as the State Government may prescribe, the Collector may suspend or cancel and forfeit the Security Deposit/Earnest Money Deposit of any mining lease or

retail license or movement permit in the following circumstances after giving reasonable opportunity of being heard -

- a) if the mining lease or license or movement permit is transferred or sublet by the holder thereof; or
- b) if any mining revenue payable by the holder thereof is not duly paid; or
- c) in the event of any breach by the holder of such mining lease, any license or movement permit or by his servant or agent, or by any one acting on his behalf, with his express or implied permission, of any of the terms and conditions of such mining lease, any license or movement permit; or
- d) if the holder of mining lease or any license or movement permit or his agent or employee is convicted of an offence punishable under the Act or these Rules or any other law for the time being in force, relevant and connected with mining matters or matter relating to mining revenue or of any cognizable and non-bailable offence under any other relevant law; or
- e) if the purpose for which the mining lease, the license or movement permit was granted ceases to exist; or
- f) if the mining lease, the license or movement permit has been obtained through misrepresentation or fraud; or
- g) If the Settlee/license holder has violated any of the conditions mentioned in these rules; or
- h) If the Settlee/licensee fails to obtain the environmental clearance within three months or violates any of the condition mentioned therein; or
- i) If the Settlee/licensee fails to start mining operation within three months from the date of signing the Agreement; or
- j) If, for any other reason, the Collector is prima facie satisfied, that the mining lease or the license or the movement permit is fit to be cancelled.

(3) For any action taken under subsection (1), the Settlee/licensee shall not be eligible for any compensation or refund or deposit whatsoever.

(4) Notwithstanding anything mentioned above, in case of detection of any violation of the Act, these rules and any other condition of the mining lease or any license or movement permit, the State Government or the Collector may, apart from cancelling the mining lease/license/movement permit, also impose suitable financial penalties and/or criminal prosecution.

(5) Any such penalties levied shall be recoverable under the Public Demand Recovery Act, 1914 (Act 4 of 1914).

- 57. Procedure for Cancellation of any Lease or License.** - (1) Upon receipt of a report from any Mining Officer regarding any contravention of the Act or these rules, the Collector shall issue a notice to the said Settlee/licensee giving 15 days time to file show cause.

- (2) After hearing the Settlee/licensee, the Collector shall, pass a reasoned order. In the said order, the Collector shall indicate whether the existing stock of the minor minerals and other transport should be confiscated and auctioned or not, and whether or not, the money so received is to be returned to the Settlee.
- (3) The Collector may also direct the Settlee that such stock, pursuant to the cancellation or suspension of the mining lease or the license, be deposited with the Corporation at such a price as the Corporation may decide. If the Settlee/licensee fails to implement the order of the Collector, the Collector shall cause the minor minerals to be deposited with the Corporation and recover the cost from the said Settlee/licensee.
- (4) Where the Settlee/licensee fails to appear as a result of the said notice, the Collector shall be free to pass an order ex-parte.
- 58. Bar to the Right of Renewal and to Compensation.** – No person to whom a mining lease or any license or movement permit has been granted earlier shall be entitled to claim any renewal thereof as a matter of right, and no claim shall lie for damages or otherwise in consequence of any refusal to renew a mining lease or the license or movement permit on the expiry of the period for which the same remains in force.
- 59. Power of the State Government to withdraw or not to renew all or any license.** – (1) The State Government may at any time decide either to withdraw or not to renew all or any of Mining Lease or Retail license or any other license issued to any Settlee/licensee in the entire State of Bihar or any part thereof.
- (2) For any action taken under sub-section (1), nothing shall be paid in consequence thereof, except any retail license fee or deposit paid in advance after deducting any amount recoverable by the Government.
- 60. Power of the Collector to take over the Management.** – If any Settlee/licensee or any holder of a retail license issued under these Rules contravenes any provision of the Act or any rules made there under or defaults in complying with any condition imposed upon him or upon refusal to abide by such reasonable directions as the Collector may issue under these rules, or upon expiry of the mining lease period or retail license or withdrawal of the retail license, the Collector, may at any time, with or without cancellation of such mining lease or retail license or privilege –
- take over the management of such mining operations at the risk and loss of the owner of that establishment; or
  - take over the management of such establishment at the risk and loss of the owner of that establishment; or
  - transfer the establishment, for the unexpired period of the mining lease or retail License or the privilege, at the risk and loss of the owner, to any other person or the Corporation.
- 61. Power of Collector to Requisition Minor Minerals.** – (1) Notwithstanding anything mentioned above, in case of any natural



disaster or acute shortage or such other emergencies or in order to maintain a buffer stock, the Collector may require a Settlee/licensee to produce or excavate a specified output of the minor mineral and deliver it to such a place at such rate as he deems fit.

(2) Notwithstanding anything mentioned above, in case of any natural disaster or acute shortage or such other emergencies, the Collector may require a retail licensee to deliver a specified quantity of any minor mineral and deliver it to such a place at such rate as he deems fit.

**62. Exit Option for Settlee or Retail Licensees.** – (1) Any Settlee/licensee or Retail Licensee, at any point of the mining lease period or the Retail license period, as the case may be, may opt to exit the business upon giving three months' notice to the Collector. However, this option is not available to Settlees who have not paid their bidding amount or settlement amount or have violated any condition of lease/license.

(2) The Collector may allow such Settlee/licensee to exit the business and return any security money deposited by the Settlee/licensee after deducting such dues as are recoverable.

(3) The Collector, thereupon, shall initiate arrangement for a fresh bidding or a fresh retail license, as the case may be.

(4) In case of fraud or violation of mining or environmental conditions or any other irregularities reported, no exit option will be available to the Settlee/licensee and their security deposit shall be forfeited.

**63. Power of the Collector to issue directions.** – (1) Where a Mining Lease has been cancelled or proposed to be cancelled, the Collector may direct the Settlee to continue to excavate or produce such minor mineral in such quantity and deposit the same at such a place, as he may specify in the order, till alternative arrangements are made.

(2) Notwithstanding anything mentioned in Sub Rule (1) above, the Collector can issue any direction to any Settlee/licensee to do or not to do a specific action so as to ensure that the minor minerals in the district are available at the prescribed rates and there is no violation of the provisions of the Act and these Rules.

**64. Power Of The Mines Commissioner To Suspend/Cancel Mining Lease or Retail License.** - Notwithstanding anything contained in this Chapter, the Mines Commissioner, on his own or upon a complaint or upon a report by any Mining Officer or Police Officer, may initiate steps to cancel or suspend any mining lease or retail license or any other license /movement permit issued under these rules;

Provided that he shall give a reasonable opportunity to such Settlee/Licensee to present his case, before passing any order.

## **CHAPTER X MINING REVENUE.**

**65. Nature and components of Mining Revenue.** – Mining Revenue shall be levied and recovered under the following heads, namely:-

- (a) Bidding Proceed
  - (b) Fee from Retail Licenses
  - (c) Royalty
  - (d) Special Duty
  - (e) Fee from Permits, including Movement permits etc
  - (f) Seigniorage Fee
  - (g) Accruals through fines, penalties and other sundry receipts etc; and
  - (h) Any other duty, fee or surcharge as the State Government may, by notification, impose.
- 66. Mining Revenue to be paid irrespective of pendency of any Writ Petition, Suit, etc.** – Notwithstanding that a Writ Petition has been preferred or a suit or other Proceeding has been instituted in any court or any appeal has been filed before any Tribunal or the Mines Commissioner or a Revision has been filed before the State Government, any sum due to the State Government under the Act or these rules as a result of demand or order made or passed by any Officer or Authority empowered in this behalf by or under the Act or these rules, shall be payable in accordance with such demand or order unless and until such payment has been stayed by the Competent Authority or the Court.
- 67. Power to impose fee on import, export, transport and excavation.** -(1) Any fee or surcharge, as the case may be, at such rate or rates as the State Government may direct, may be imposed, either generally or for any specified local area on -
- (a) any Minor minerals imported, or
  - (b) any Minor minerals exported, or
  - (c) any Minor minerals transported, or
  - (d) any Minor minerals excavated under any mining lease issued or renewed under this Act, or
  - (e) any Minor minerals excavated or produced in any Mine or crusher.
- (2) A duty, at such rate or rates as the State Government may direct, may be imposed, either generally or for any specified local area, on any Minor Minerals under the provisions of these rules.
- 68. Royalty from Minor Minerals.** – (1) All minor minerals shall be subject to a royalty to be paid by the user at a rate decided by the State Government and as revised from time to time.
- (2) All the royalty may also be collected by the Corporation and deposited with the State Government every month.
- (3) The Department may lay down such other guidelines as may be required for mechanism for collection of Royalty.
- 69. Seigniorage Fee from Government Projects.** – (1) All the Government Departments, particularly Works Departments using any minor mineral for their schemes or projects, shall deduct a Seigniorage Fee from their suppliers or contractors of such minor minerals.

(2) Such Seigniorage Fee shall be at a flat rate of two percent and shall be deducted by the Department from their supplier and contractor and deposited with the Mining Officer of the district.

Provided that the State Government may increase or decrease the Seigniorage Fee from time to time.

- 70. Furnishing of Return.** -(1) Every Settlee/Licensee/ shall furnish a true and complete return in respect of all his transactions relating to mining activities, mineral extraction and dispatches of minerals and any other transactions prescribed specially for each month to the prescribed authority in such form and in such manner as may be prescribed.
- (2) If Settlee/Licensee/ fails to furnish the return within the time specified, he shall be prosecuted under the provision of these rules.
- 71. Electronic Filing of Returns, Payment by Challan or Statement.** - The Mines Commissioner may require by notification any class of Settlee/Licensee/ to file returns, payment challan or statements electronically. In case such a notification is issued, the class of lessee/Settlee/Licensee/ specified therein has to compulsorily file their returns, payment challan or statements electronically on the specially designed site or portal of the Department.
- 72. Payment of Royalty and Interest thereon.** Every Settlee/licensee shall make the payment of royalty due to be paid as in the manner prescribed through challan/e-Challan. In case of defaults in making payments on the due date, they will be liable to pay interest in the manner prescribed. Interest being a civil liability, the issuance of notice is not required for the purpose of levy. In fact, under circumstances warranting payment of interest, the Settlee/Licensee is supposed to compute it suo motto, pay the same and furnish the challan evidencing such payments.
- 73. Scrutiny of Return.** - (1) The Mining Officer shall, within the time and in the manner prescribed, scrutinize every return and payment for the purpose of ascertaining that –
- all calculations contained therein are arithmetically accurate;
  - the amount of royalty, Seigniorage Fee, extraction of minerals, royalty payable and interest payable, if any, have been computed correctly or properly.
  - Evidence as prescribed has been furnished with regard to payment of royalty and interest payable, if any;
- (2) If upon scrutiny under sub-Section (1), the Mining Officer discovers any errors, he will serve a notice in the prescribed form on the concerned Settlee/licensee directing him to pay the due royalty or interest within 7 days.
- (3) The prescribed authority is satisfied that reasonable ground exists to believe that any Settlee/licensee has furnished a wrong return with an intention to evade the royalty, the prescribed authority shall after giving him a reasonable opportunity of being heard, assess to the best of its judgment, the amount of royalty due, if any, from the Settlee/licensee.

(4) In case the Settlee/licensee or the Retail licensee fails to obey the orders passed by the Mining Officer, he shall be prosecuted under Rule 80.

- 74. Single Bank Account.** - (1) All Settlee/Licensee shall necessarily operate only a single bank account for all their operations connected with the said lease or the Retail license or the movement permit.  
 (2) The Settlee/licensee must necessarily give the information of the said bank account to the Collector, the Mining Officer of the district, Director Mines and the Mines Commissioner.  
 (3) Any person who acts in violation of this provision shall be prosecuted under Rule 80.

## CHAPTER XI

### OFFENCES AND PENALTIES.

- 75. Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.** - Whoever, in contravention of Section 4(1) and Section 4(1A) of the Act or these rules or order made or notification issued under the Act or these rules or in contravention of any condition of any mining lease or retail license or movement permit or any other license under these rules or without a valid mining lease or retail license or movement permit or any other license issued under these rules -

- (a) excavates, produces, possesses, buys, sells, distributes, collects, imports, exports, or transports any minor mineral, or
- (b) transports the minor minerals far in excess of the authorized carrying capacity of the vehicle or transport, or
- (c) indulges in the excavation, production, transport or trade of any minor mineral in a manner so as to endanger the life of any person working in the mining area or outside or neighborhood,
- (d) constructs, establishes any plant & machinery or crushers;

Shall be punishable with imprisonment for a term of five years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

**Explanation-** For the purposes of this section, any owner of the transport or the Settlee of the minor mineral may also be prosecuted if it is established that such contravention is happening with full knowledge of such owner or Settlee, in addition to the driver of the transport.

- 76. Commission of offence by Companies.** - (1) If the person committing an offence under these rules is a Company, the Company as well as every person in charge of and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of commission of the offence, shall be deemed to be guilty of offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that where a company has different establishment or branches or different units in any establishment or branch, the concerned Chief Executive and the person in charge of such establishment, branch, unit nominated by the company as

responsible for the conduct of business shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit:

Provided further that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary, or other Officer of the company, such director, Manager, Secretary or other Officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) This section shall not apply to such companies where the majority shareholding is held by Central or any State Government or such companies as the State Government may exempt.

**Explanation** – For the purpose of this section –“Company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and “Director”, in relation to the firm, means a partner in the firm.

**77. Presumption as to Commission of offence in certain cases.** – (1) In prosecution under any relevant provision of these rules, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the accused person has committed the offence punishable under that section in respect of any minor mineral, for the possession or manufacture or excavation or transportation of which he is unable to account satisfactorily.

**78. Penalty for mixing foreign ingredients in minor minerals.** – Whoever, mixes or permits to be mixed with any foreign ingredient in any minor minerals with an intention to reduce its quality shall be punishable with imprisonment which shall be for a term of five years and fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to five lakh rupees;

**79. Order by Collector to pay compensation.** – Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Collector, while passing an order under these rules may, if he is satisfied that any person or his property has suffered damaged due to action of the Settlee/licensee, order to pay, by way of compensation, a suitable amount to such person:

(2) in case of non-payment by the Settlee/licensee, the said compensation amount within the specified time, the Collector may pay the said amount to the person and thereafter recover the said compensation as “Public Demand” under the Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914).

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the High Court:

Provided that no appeal can be filed against any order filed under this Rule unless 50% of the amount ordered to be paid under sub-section (1) is deposited by the Appellant in the Court:

Provided further that the High Court may entertain an appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the Appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

- 80. Penalty for misconduct by Settlee, Licensees, etc.** – Whoever being a stake holder or a holder of a mining lease or retail license or movement permit granted or issued under these rules or being in the employment of such holder and acting on his behalf, -
- (a) Fails to produce such Agreement or license or movement permit on demand by any Mining Officer, Police Officer or any other officer duly empowered to make such demand; or
  - (b) Willfully does or omits to do anything in contravention of the conditions of the mining lease or retail license or movement permit not otherwise provided in these rules; or
  - (c) Fails to cooperate during the inspection by any Mining Officer of his premises; or
  - (d) willfully disobeys the lawful order passed by any Mining Officer or the Collector; or
  - (e) Fails to submit returns.
- shall, be punished -
- (i) In the case of an offence falling under clause (a), with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees.
  - (ii) In the case of an offence falling under clause (b) (c) (d) & (e), with an imprisonment for a term which shall not be less than two years but may extend to five years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.
- 81. Penalty for employing minors in Mining or Mining trade.** - If any person employs any minor below the age of eighteen years for the purposes of excavating, producing, selling, possessing, transporting, or distributing any minor mineral, he shall be punishable with a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to five lakh rupees.
- 82. Penalty for assault and obstruction.** – Notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860), any person who assaults or threatens to assault or obstructs or attempts to obstruct any Mining Officer or Police Officer or any other officer in the discharge of his official duties shall be punishable with a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to five lakh rupees.
- 83. Penalty for non-Payment of Royalty, Duty or Fee.** – If any person fails to pay any royalty duty or fee, which under these rules he is liable to pay, he shall be punishable with imprisonment for a term

- which shall not be less than three years but which may extend to five years and also with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.
- 84. Penalty for allowing premises, etc, to be used for Commission of an Offence.** – Whoever, whether being a Settlee/licensee under these rules or otherwise, and having the control or use of any house, room, enclosure, space, animal or conveyance, knowingly permits it to be used for commission by any other person of an offence punishable under any provision of these rules, shall be punishable in the same manner as if he had himself committed the said offence.
- 85. Penalty for attempt to commit an offence.** – Whoever attempts to commit an offence punishable under these rules shall be liable for half the maximum punishment provided for the offence under these rules.
- 86. Penalty on Mining Officer or Police Officer refusing to do duty.** – Any Mining Officer or Police Officer who, without lawful excuse, refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office, unless expressly allowed to do so in writing by the Mines Commissioner or Collector, or unless he shall have given to his official superior officer two months' notice in writing of his intention to do so, or who shall be guilty of cowardice shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.
- 87. Penalty for offences not otherwise provided for.** – Whoever does any act in contravention of any of the provisions of these rules or any rule or order made there under and punishment for which has not been otherwise provided for such contravention, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees or both.
- 88. Enhanced punishment after previous conviction.** – If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under these rules, subsequently commits and is convicted of an offence under these rules, he shall be liable to twice the punishment, provided for the first conviction.
- 89. Non-compounding of offences.** – Any offence committed in contravention of the provisions of the Act and these rules shall be non-compoundable.

## CHAPTER XII

### CONFISCATION ETC BY COLLECTOR.

- 90. Things liable for confiscation.** – Whenever an offence has been committed, which is punishable under the Act and these rules, following things shall be liable to confiscation, namely -
- a) Any minor mineral,
  - b) Any plant and machinery,

- c) Any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for carrying or excavating or producing or manufacturing any minor mineral.
- d) Any land and/or premises or part thereof that may have been used for storing or producing or excavating any minor minerals.

**91. Procedure for Confiscation and Auction of Minor Minerals by District Collector. -**

(1) Where any minor mineral is seized by any Mining Officer or Police Officer, he shall submit report to the District Collector and request for its confiscation and auction.

(2) On receipt of the report under sub-section (1), the District Collector, if satisfied that an offence under these rules has been committed, may, whether or not prosecution is instituted for the commission of such an offence and whether or not a case is pending before any Court, proceed for confiscation and auction of such minor mineral;

(3) The Collector shall thereupon issue a public notice informing about the impending auction giving 7 days notice for any person to appear and file objection with regard to the said bidding.

(4) If within 7 days no objection is received, the Collector shall treat the said minor minerals as "unclaimed" and then proceed to order confiscation of the said minor mineral. Thereafter, he shall issue a public auction notice giving 7 days time for prospective bidders and then settle the auction with the highest bidder. The proceeds shall then be deposited in the Government Treasury. Before deciding the auction, the Collector may direct that a certain portion of the confiscated minor mineral may be given to the local Government Departments at their Scheduled rates. The remaining portion of the confiscated minor mineral may be given to the highest bidder.

(5) Where, as a result of the public notice issued under sub Rule (2) any objection is filed by a person who claims that the confiscated minor minerals belong to him, the Collector shall pass a reasoned order rejecting or accepting his claim. If the claim is rejected by the Collector, then he may proceed to take action for auction as per sub Rule (4). However, the Collector may deposit the proceeds in the Government Treasury with the condition that if the objector goes in appeal and obtains an order in his favor from any Court, the said money shall be returned to the objector.

(6) Where, as a result of objection received by the Collector, the Collector passes an order in favor of the objector and holds that the confiscated minor minerals belongs to the objector, the Collector may, in the interest of ensuring adequate availability of the said minor minerals in the



district, still proceed with the auction process as per sub rule (4) and money so fetched in the auction be given to the claimant..

(7) Where, pursuant to his order under sub Rule (6) above, if the minor mineral so confiscated is a subject matter of an FIR or a criminal proceeding, the Collector may still proceed with the auction but deposit the proceeds in the Government Treasury with the condition that if any objector goes in appeal and obtains a favorable order from any Court, the said money shall be returned to the said person.

(8) The District Collector shall submit a full report of all particulars of confiscation to the Commissioner of Mines within one month of such confiscation

**Explanation.** – For the purpose of this rule, the public auction may or may not be through e-auction.

**92. Procedure for Confiscation and Auction of Items other than Minor Minerals by District Collector. -**

(1) Where anything, other than a minor mineral, liable for confiscation under these rules is seized or detained under the provisions of these rules, the officer seizing and detaining such item or transport or vessel or animal shall, without any reasonable delay submit a report to the District Collector who has jurisdiction over the said area;

(2) On receipt of the report under sub-section (1), the District Collector if satisfied that an offence under these rules has been committed, may, whether or not prosecution is instituted for the commission of such an offence and whether or not a case is pending before any Court, proceed for confiscation and auction of such property;

(3) The Collector shall, before passing an order under subsection (2), give a notice of 7 days to the person concerned, of being heard and he may also issue a public notice for him to appear;

(4) If the said person appears and files his reply, the Collector shall pass a reasoned order on the same accepting or rejecting his claim. If the Collector rejects his claim, he shall order for the confiscation of the said items and its public auction.

(5) Where the person concerned does not appear as result of the notice, the Collector shall be free to pass an order ex-parte.

(6) While making an order of confiscation under sub-section (4), if the District Collector is of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, he may order the said confiscated item or any part thereof to be sold by public auction and proceeds deposited with the State Government;

(7) The District Collector shall submit a full report of all particulars of confiscation to the Commissioner of Mines within one month of such confiscation.

**Explanation.** – For the purpose of this rule, the public auction may or may not be through e-Auction.

- 93. Confiscation in Public interest or emergent cases or to prevent hoarding.** – Where the Collector feels that there is a shortage of particular minor mineral or in the event of natural disaster or in the event of a Settlee or Licensee suddenly abdicating his mining/manufacturing activity or hoarding the minor minerals, the Collector may -
- (a) Summarily confiscate such duly excavated/manufactured minerals and sell the same through public auction or to the Corporation and pay the said amount to the said Settlee; or
  - (b) Direct the Settlee to immediately sell such excavated/manufactured minor minerals in the open market or to the Corporation at the rates fixed by the Corporation so as to ensure its availability; or
  - (c) Direct the Settlee to immediately sell such minor minerals to such Government Departments at their Scheduled rates.
- 94. Power to Freeze Bank Account.** – (1) Where the Collector, upon a report by Mining Officer or Police Officer has reason to believe that the bank account of any Settlee/licensee has to be frozen in order to protect Government revenue or to assist the prosecution, he shall forth with issue an order directing the concerned bank to freeze the bank accounts of such Settlee/licensee, till further orders.
- (2) Any bank or its employee who refuses to obey the aforementioned direction of the Collector shall be prosecuted under Rule 80.
- 95. Requirement of Exhibit.** – (1) Where any minor mineral or any other item has been confiscated and criminal prosecution has been launched, such minor minerals may still be auctioned by the Collector keeping adequate evidence, in the form of an inventory drawn by an Executive Magistrate, photographs or video graphs, as a proof, for the use as an exhibit in the criminal prosecution.
- (2) The Collector shall cause a report to be filed before the concerned Court about the said auction and the said report shall serve the purpose of exhibit and/or evidence for the purposes of prosecution.
- 96. Power of the Collector to destroy or disassemble transport or vessel.** - Where any transport or vessel has been confiscated under Rule 92, the District Collector may order that such transport or vessel may be destroyed or may be disassembled so as to render it unfit for any further use.
- 97. Order of confiscation and destruction not to interfere with other punishment.** –The order of any confiscation under Rule 91 & 92 shall not prevent imposition of any order punishment to which the person affected thereby is liable under these rules.
- 98. General.** – (1) Notwithstanding anything contained in this Chapter, the Collector may direct any Settlee or licensee or any claimant to any confiscated minor minerals to deposit the said confiscated minor minerals with the local warehouse of the Corporation at such rates as the Corporation may decide. If the Settlee/licensee or the Retail licensee fails to implement the order of the Collector, the Collector

shall cause the minor minerals to be deposited with the Corporation and recover the cost from the said Settlee/ licensee.

(2) The Collector may, after having confiscated any minor mineral, cause it to be sold to such Government Departments at their Scheduled rates so that the Government projects and schemes do not suffer due to non-availability of any minor mineral

(3) All the auctions conducted in this Chapter may or may not be through e-Auction mode and the Collector shall be competent to decide the same.

(4) The Collector, if he is so satisfied, may approve a single bid received in such an auction.

### CHAPTER XIII

#### DETECTION, INVESTIGATION AND TRIAL OF OFFENCES.

**99. Power to enter, inspect, search and seize.** - (1) Any of the following Officers namely:

- (a) The Mines Commissioner, the Director Mines; or
- (b) The Collector; or
- (c) Any Block/Anchal Level Officer and above of the District authorized by the Collector; or
- (d) Any Mining Officer; or
- (e) Any Police Officer not below the rank of Assistant Sub Inspector;

may, without warrant, but subject to such restrictions as may be prescribed by the State Government, enter, inspect, search any place at any time, day or night, and seize any document, sample, equipment, conveyance, animal, commodity, minor mineral, material, raw material or any other item of concern.

(2) The Officers mentioned in sub section (1) above shall be fully empowered to use such reasonable force for the purposes of entering, inspecting, searching and making such seizures as necessary.

**100. Power to stop and check any carrier, transport or vessel.** - (1) Any Mining officer or any Police Officer not below the rank of Assistant Sub Inspector may stop any carrier, vehicle or transport or vessel to check for verification of the contents.

(2) Such Officer may require the driver of the carrier, vehicle, vessel, transport to take such carrier, vehicle, vessel or transport to the nearest weighbridge and get the contents weighed at the expense of the driver or the owner of such vehicle, carrier, vessel, transport.

(3) If any person who refuses to obey the lawful command of such Mining Officer or such Police Officer, shall be prosecuted under Rule 75 of these Rules.

**101. Power to arrest or detain without warrant.** - (1) Any of the Officers mentioned in Rule 99 may arrest or detain, without warrant, any person and/or any vehicle, animal, means of conveyance, at any time of day and night, found committing an offence or attempting to commit an offence punishable under any provision of this Act.

(2) All arrests made under this section must be reported to the Collector forthwith.

- 102. Offences to be Cognizable and Non-Bailable.** – (1) All offences under these rules shall be Cognizable and Non-Bailable and provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) shall apply.  
(2) No Court shall take cognizance of any offence punishable under the act or these rules except upon to complaint in writing made by any Officer mentioned in Rule 99.
- 103. Power to investigate.** – (1) Any Mining Officer or Police Officer not below the rank of Assistant Sub Inspector may investigate any offence punishable under this Act.  
(2) The Investigating Officer, for the purposes of these rules, shall exercise the powers of the Code of Civil Procedure 1908(No. 5 of 1908) in respect of matters enforcing the attendance of any person, examining him on oath or affirmation and compelling production of documents.
- 104. Powers of the Mining Officer.** - (1) All Mining Officers mentioned in Rule 99 shall exercise the powers of the Officer-in-Charge of a police station in his area of jurisdiction for the purposes of these rules.  
(2) The area to which a Mining Officer is empowered under Rule 99 shall be deemed to be a police station.
- 105. Production of Persons arrested.** – Any person arrested under this Act shall be produced before the Court within twenty four hours.
- 106. Reports of Arrests, Seizures and Searches.** – Every Police Officer upon making any arrest, search or seizure shall submit a report to the Collector and to the Mining Officer empowered under Rule 99 within twenty four hours.
- 107. Trial by the Court.** - In terms of the powers conferred under Section 30C of the Act, all offences punishable under this Act shall be tried by the Court of Sessions.
- 108. Special Courts.** – (1) In terms of power conferred under Section 30B of the Act, the State Government may, if consider necessary in the public interest, for the purposes of trial of all or any of the offences under this Act, either appoint or designate in every District of the State, Special Court(s) in consultation with the Chief Justice of the High Court.  
(2) The Special Court shall be presided over by a Special Judge who is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge under the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974).  
(3) The trial under this Act of any offence by the Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference to the trial of such other case.
- 109. Procedure and Power of the Special Judge.**- (1) A Special Judge may take cognizance of offences without the accused being committed to him for trial and, in trying the accused persons, shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), for the trial of warrant cases by the Magistrates;

- (2) Save as provided in sub-section (1), the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as they are not inconsistent with this Act, apply to the proceedings before a special Judge; and for purposes of the said provisions, the Court of the special Judge shall be deemed to be a Court of Session and the person conducting a prosecution before a special Judge shall be deemed to be a public prosecutor;
- (3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (2), the provisions of Sections 326 and 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to the proceedings before a special Judge and for the purposes of the said provisions, the special Judge shall be deemed to be a Magistrate;
- (4) A Special Judge may pass upon any person convicted by him any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted;
- (5) A Special Judge, while trying an offence punishable under this Act, shall exercise all the powers and functions exercisable by a District Judge under the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 (Ord.38 of 1944);
- (6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the special Judge shall, as far as practicable, hold the trial of an offence on day-to-day basis.
- 110. Power to transfer cases to Regular Courts.** - Where, after taking cognizance of any offence in these rules, a Special Court is of the opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for the trial of such offence to any Court having jurisdiction under the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974) and the Court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it had taken cognizance of the offence.
- 111. Power of the Special Court to implead manufacturer, owner, occupier, etc.** - Where at any time during the trial of an offence under these rules, alleged to have been committed by any person, not being the lessee, licensee, manufacturer, or transporter of any mineral or owner or occupier of any premises involved in the offence, the Special Court is satisfied, on the evidence adduced before it, that such manufacturer, distributor, dealer, owner or occupier is also concerned with that offence then the Court may notwithstanding anything contained in the sub-section (3) of section 319 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), proceed against him under any Section of this chapter.
- 112. Special/ Additional Public Prosecutors.** - (1) For every Special Court set up under Section 30C of the Act, the State Government, as per the procedure laid down under Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974), may appoint a person to be the Special Public Prosecutor and more than one person to be Additional Public Prosecutors.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub Rule (1) above, the Government may appoint a Special PP for every district from amongst the panel prepared by the District Magistrate in consultation with the Session Judge.
- (3) A Special/Additional PP so appointed under sub Rule (2) above, may be removed upon the report of the District Magistrate.
- 113. Appeal.** – Any person aggrieved by any order of the Special Court may, within forty five days from the date of order, prefer an appeal in the High Court.
- 114. Procedure for launching Prosecution.** – (1) As soon as a violation of any of the provisions of these rules is detected, the Mining Officer or the Police Officer of the rank of Assistant Sub Inspector and above, shall register a case under the Act and these rules.
- (2) The Mining Officer or police officer concerned shall then proceed for investigation of the case.
- (3) After investigation of the case, he shall file a Report within Sixty – Days from the date of registration of the case.
- (4) The Report so filed shall be deemed to be a Police Report for the purposes of Section 173(2) and Section 190 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974).
- (5) The Collector shall ensure that the aforementioned Report is filed in time and shall also monitor effective prosecution of the cases before the Courts.
- (6) The Superintendent of Police shall closely monitor the status of cases filed by the Police Officers under this Act and shall submit period reports to the Mines Commissioner and the Collector.

#### CHAPTER XIV

#### APPEALS AND REVISION.

- 115. Appeals.** – (1) All final orders passed by any Mining Officer other than the Mines Commissioner or Collector under these rules, shall be appealable to the Collector within sixty days from the date of the order.
- (2) All final orders passed by the Collector shall be appealable to the Divisional Commissioner within ninety days from the date of the order complained of.
- (3) All final orders passed by the Mines Commissioner shall be appealable to the Board of Revenue within ninety days from the date of the order complained of.
- (4) All appeals shall be disposed of within three months from the date of the filing.
- 116. Revision.** – (1) All final orders passed by the Collector in appeal shall lie in revision before the Mines Commissioner.
- (2) All final orders passed by Divisional Commissioner in appeal shall lie in revision before the Mines Commissioner.
- (3) All Revision matters must be disposed of within two months from the date of the filing.
- (4) The State Government may, on its own motion or on an application made to it, call for and examine the records of any

proceeding before any Mines Officer or any document, including that relating to renewal or refusal of retail license or grant of movement permit, pass etc under these rules, for the purpose of satisfying itself as to the correctness and legality of any order passed in, and as to regularity of, any such proceeding and may, when calling for such record, direct that the order be not given effect till the pendency of the examination of the record, so called for. After examining the record, the State Government may annul, reverse, modify or confirm such order, or pass such other order as it may deem fit.

- 117. Review.** – Notwithstanding anything contained in this Chapter, the State Government may at any time review its own decision.

#### **CHAPTER – XV ENFORCEMENT.**

- 118. State Level Mining Task Force.** – (1) There shall be constituted a State Level Mining Task Force as under:-

- (a) Chief Secretary-Chairman
- (b) Development Commissioner- Member
- (c) Principal Secretary Home – Member
- (d) DG Police – Member
- (e) Principal Secretary, Environment and Forest
- (f) Principal Secretary, Revenue and Land Reforms
- (g) Principal Secretary, Industries
- (h) Principal Secretary, Road Construction Department
- (i) Principal Secretary, Building Construction Department
- (j) Principal Secretary, Rural Works Department
- (k) Principal Secretary, PHED
- (l) Principal Secretary Commercial Taxes Department
- (m) Chairman State Pollution Control Board
- (n) Principal Secretary, Mines and Geology Department
- (o) Director Mines – Member Secretary

(2) The Chief Secretary may co-opt or invite any other Officer or expert to attend and contribute in the meeting of the State Level Mining Task Force. Half of the Members present shall constitute the quorum.

- 119. Monitoring Committee.** - The State Level Mining Task Force shall constitute a Monitoring Committee headed by the Principal Secretary of the Department of Mines and Geology with such members as it may deem fit. The Monitoring Committee shall ensure the compliance of the directions of the State Level Mining Task Force.

- 120. Function of State Level Mining Task Force.** - The State Level Mining Task Force shall insure implementation of these Rules and shall monitor the excavation, trade and availability of minor minerals in the State. In addition to the above, it shall also

- (a) provide guidance to the Department for achieving the objective of the Act and these Rules
- (b) frame policies and guidelines essential to implement these Rules
- (c) issue direction to any other Department to undertake such action as essential to achieve the objective of the Act and these Rules.

(d) Shall ensure that the mining activity is undertaken as per the environmental safeguards laid down by the Ministry of Environment Forest and Climate Change.

**121. Divisional Level Mining Task Force.** – (1) There shall be constituted a Divisional Level Mining Task Force as under :-

- (a) Divisional Commissioner – Chairman
  - (b) Divisional Commissioners of the Bordering Divisions – Co-Chairmen
  - (c) DIG Police of the Division.
  - (d) DIG Police of the Bordering Divisions
  - (e) The Conservator of Forest
  - (f) All Collectors of the Division
  - (g) All SPs of the Division
  - (h) All DFOs of the Division
  - (i) All Mining Officers of the Division
  - (j) Secretary to the Divisional Commissioner – Member Secretary
- (2) Additionally, the Divisional Commissioner may co-opt such additional members as he may deem fit. The Divisional Commissioner may also invite the Collectors and the SPs of the districts who share boundaries with the Division.
- (3) Half of the Members present shall constitute the quorum.
- (4) It shall meet once in a month.

**122. Function of the Divisional Level Mining Task Force.** – The Divisional Level Mining Task Force shall insure implementation of these rules and shall monitor the excavation, trade and availability of minor minerals in the Division. In addition to the above, it shall also –

- (a) ensure the inter-district coordination between the districts of the Division and the bordering districts of Division.
- (b) Prepare and launch coordinated action plan to check illegal mining and illegal transportation of minor minerals across districts and districts outside the Division.

**123. District Level Mining Task Force.** – (1) There shall be a constituted a District Level Mining Task Force as under:

- (a) Collector – Chairman
  - (b) Superintendent of Police
  - (c) All Sub Divisional Officers
  - (d) All Sub Divisional Police Officers
  - (e) Divisional Forest Officer
  - (f) Executive Engineer, RCD, BCD, PHED and Rural Works Department
  - (g) District Transport Officer
  - (h) District Mining Officer – Member Secretary
- (2) The Collector may co-opt or invite any other Officer or expert to attend and contribute in the meeting of the District Level Mining Task Force.
- (3) Half of the Members present shall constitute the quorum.



(4) It shall necessarily meet once a month and at earlier frequencies as directed by the Department.

- 124. Function of the District Level Mining Task Force.** - The District Level Mining Task Force shall insure implementation of these rules and shall monitor the excavation, trade and availability of minor minerals in the district. In addition to the above, it shall also
- ensure that all the mining activity is carried on as per the condition of the mining lease.
  - ensure that no illegal mining, illegal transportation, over loading, hoarding and black marketing of minor mineral is carried on.
  - all the retail business of minor minerals are carried out as per the provision in these rules.
  - issue direction to any other Department to undertake such action as essential to achieve the objective of the Act and these Rules.
  - Shall ensure that the mining activity is undertaken as per the environmental safeguard laid down by the Ministry of Environment Forest and Climate Change.

## CHAPTER - XVI

### DISTRICT MINERAL FOUNDATION.

- 125. District Mineral Foundation.** - (1) There shall be a District Mineral Foundation as mentioned under section 9B of the Act.
- (2) All Settles/licensee, as required under section 15A of the Act, shall be required to contribute 2% of the bidding proceeds or the license fee to the District Mineral Foundation in which they are undertaking mining operation or Retail operation. If the area operation extent to two district then they shall contribute two percent
- (3) The District Mineral Foundation shall be a Trust as required under section 9B of the Act.
- 126. Trust and its Constitution.-** (1)
- There shall be constituted for each District of Bihar, a Trust established in terms of sub-section (1) of Section 9 (B) of the Act to be known as the District Mineral Foundation for the said District;
- (2) The Trust shall be perpetual body and shall have a common seal.
- (3) Each of the Foundation shall have it's Headquarter at the respective District Headquarter
- 127. Composition of Board of Trustees of the District Mineral Foundation. -** (1)

The District Mineral foundation in each of the district shall consist of the following members namely:-

|   |                  |
|---|------------------|
| Collector   | Chairperson      |
| Additional Collector  | Co-Chairperson   |
| Assistant Director Mines/ Mineral Development Officer/Mines Inspector | Member Secretary |
| Director, District Rural Development Agency                           | Member           |
| Divisional Forest Officer   | Member           |
| Civil Surgeon   | Member           |
| District Welfare Officer  | Member           |

|   |         |
|---|---------|
| District Co-Ordinator, Jeevika  | Member  |
| District Accounts Officer   | Member  |
| District Cooperative Officer  | Member  |
| Any other officer authorized by the Collector.  | Member  |
| Two Representatives,( One from Major Mineral & Other from Minor Mineral) from the holders of Mineral concession belonging to the concerned district | Members |
| Any person from mining affected area, nominated by the Collector  | Member  |

(2) The Chairperson may invite such other officials to the meetings of the Foundation, as he/she may consider necessary.

(3) The quorum for the Foundation shall be fifty percent of the members.

(4) The Foundation shall meet at least once every quarter and more frequently if required, and accordingly take decisions regarding utilization of the Fund in an effective, transparent and accountable manner. The Chairperson shall arrange for the maintenance of the books of accounts of the Fund.

**128. Objectives of the Foundation.** - The District Mineral Foundation shall work for the interest and benefits of the people and areas affected by mining related operations in the districts in such manner as may be prescribed by the State Government in order to meet the following objectives:-

(a) To Implement various developmental and welfare projects or programs in mining affected areas.

(b) To minimize or mitigate the adverse impacts, during and after mining, on the environment, health and socio-economics of people in mining districts.

(c) To ensure long-term sustainable livelihoods for the affected people in mining areas.

(d) Funding of expenditure incurred on implementation of any scheme of incentives that the State Government may frame for recognition and awards for scientific mining undertaken with highest regard to mineral conservation, rehabilitation measures along with environmental safeguards and other measures.

(e) Implementing the objectives specified in Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (P.M.K.K.KY.)

(f) Any other objective which the State Government may consider expedient to support in the overall interest of the mining sector.

**129. Powers and Functions of the Foundation.** - The Foundation shall have the overall control over the management and functioning of the Trust and shall, subject to the guidelines or directions, if any, issued by the Government from time to time, have the powers to -

(a) Approve the annual budget and action plan for the Trust;

(b) Approve the master plan or perspective plan;

(c) Decide the priority areas and allocations;

- (d) Appoint the auditors and approve the annual reports;
- (e) Monitor the proper functioning of the Trust.
- (f) Carry out other activities as notified by the Central/State Govt. from time to time.

**130. Fund of the Trust.** - The funds of the Trust shall comprise :

- (a) Payment to the Trust made by the holders of mineral concessions at the rates specified by Central/State Government.
- (b) Payments made to the trusts by any Settlee/licensee or any other person as required by the Central Government or the State Government.
- (c) All receipts and incomes including interest accrued on the deposits made in the Bank Account.
- (d) Voluntary contributions, if any, received by the Trust from any person or Organization.
- (e) Any other grant, subvention and/or financial assistance notified for this purpose by the Government.

**131. Bank Accounts.** - The Fund shall be kept in any Scheduled Bank or a Bank designed for this purpose by the Government through a Savings Bank Account in the name of District Mineral Foundation or such name as decided by the Government in this regard and such account shall be operated under the joint signatures of at least two of the three signatories, viz. Chairperson, Co-chairperson and Member Secretary.

**132. Amount payable by the holders of mineral lease holders or Settlees/licensee to the Trust.** -

- (1) In respect of Minor Minerals an amount equal to two percent or at a rate prescribed by the State Government from time to time of the annual bidding/settlement amount/compounded royalty as per category fixed in case of brick earth/royalty payable by permit holder/royalty paid by existing mining lease holder shall be charged from the mineral concession holder on annual basis and credited to the Foundation, in addition to the amount payable to the Government on account of such concession.
- (2) The said contribution shall be remitted by the mineral concession holder by 31st December every year during the entire concession period. In case of sand settlement, the said amount shall be paid along with the installments of mining royalty.
- (3) For default in payment till prescribed date simple interest @ 24 percent per annum or as decided by the State Government shall be charged from the Mineral concession holder.

**133. Mode Of Payment of Contribution.** - All payments shall be made by way of Bank Draft drawn in favor of DMF Trust, (Name of District), Payable at (Name of the District)

**134. Expenditure/Utilization of the District Mineral Foundation Fund.** -

(1) The expenditure and utilization of fund accrued under the District Mineral Foundation shall be done as per the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (P.M.K.K.K.Y.) details of which are annexed as Annexure-I and/or in a manner as decided by the Central/State Government from time to time.

(2) The District Mineral Foundation shall abide by all guidelines and directions issued in respect of the Pradhan Mantri Khanij Kshetra kalyan Yojana (**P.M.K.K.K.Y.**) and/or other schemes by the Central/State Governments, as applicable.

**135. Maintenance and Audit of Accounts. -**

(1) The accounts of the District Mineral Foundation shall be maintained in the form, mode and manner as may be decided by the Government.

(2) The accounts of the District Mineral Foundation shall be audited in such manner as may be decided by the Government.

(3) After the audit the District Mineral Foundation shall submit the annual report to the Government.

**136. Annual Report. -**

(1) Every year, within three months from the date of closure of the Financial Year, the Foundation shall cause to prepare an annual Report on the activities of the Trust for the respective year.

(2) The Annual Report will be submitted to the Government within one month from the date of its approval by the Foundation and will also be hoisted on the website of the Foundation.

(3) The Annual Report of each Foundation shall be laid before the State Legislative Assembly.

**137. Monitoring of the amount payable to the Foundation. -**

Every lessee/Mineral Concession holder shall remit the amount payable to the Foundation into the credit of such bank account as the Government may specify. Every Officer who is authorized to collect royalty shall maintain a register of the amount payable and paid by each lessee/ Mineral Concession holder and furnish the monthly consolidated statement thereof to the Chairperson of the foundation at the end of every month.

**138. Identification of Affected Areas and People. -**

(1) Affected Areas:

(a) Directly affected areas are where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal, overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc. are located and shall include:

(i) Villages and gram Panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district on even state.

(ii) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State

Government, irrespective of whether this false within the district concerned or adjacent district.

- (iii) Villages in which families displaced by mines have been resettled or rehabilitated by the project authorities.
- (iv) Villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc.

(b) Indirectly affected areas are those areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequence due to mining-related operations. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operation, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.

(2) Affected people –

(a) the following shall be considered as directly affected persons:

- (i) 'Affected family' as defined under Section 3(c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
- (ii) 'Displaced Family' as defined under Section 3(k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
- (iii) Any other as appropriately identified by the concerned Gram Sabha.

(b) Persons affected by mining shall include people who have legal and occupational rights over the land mined, and also those with usufruct and traditional rights.

(c) Affected families shall be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of Gram Sabha or the Urban Local Body as the case may be.

(3) The District Mineral Foundation shall prepare and maintain an updated list of such affected areas and people.

## CHAPTER XVII

### EXEMPTIONS.

**139. Power of State Government to exempt minor minerals from the provisions of these Rules.** – The State Government may, by notification, either wholly or partially, and subject to such conditions (if any) as it may think fit to prescribe, exempt any minor mineral from all or any of the provisions of these rules, either throughout the

State or any specified area of the State, for any specified period or occasion or for any specified class of persons and for such purposes.

**140. Power of Government to relax the operation of any provision of these Rules.** - (1) State Government may, relax the operation of one or more of the provisions of these Rules if, in the opinion of the Government, such relaxation is necessary in public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government, in such case as it deems proper in public interest, may grant a mining lease/mining settlement and may also authorize the grant of a quarrying permit or movement permit to any person on terms and conditions other than those prescribed in these rules for reasons to be recorded in writing:

Provided that the State Government may grant a mining lease/settlement/retail license in any area under its jurisdiction to any Government Department or State owned Corporation on terms and conditions other than those prescribed in these Rules.

**141. Mining Lease etc to any Works Department.** - (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the State Government may grant license/lease to any Works Department for any particular project in a specific number of districts for specific period of time.

(2) The said Works Department shall have to pay the due royalty/Seigniorage Fee and such other fee as applicable under these rules.

**CHAPTER XVIII  
MISCELLANEOUS.**

**142. Restriction on General Ban on Mining.** - No Authority or Agency or institution or any Competent Person shall issue a general blanket ban of mining of minor minerals without consulting the State Government. If it comes to the knowledge of the State Government that such a ban has been imposed, it shall be competent to overrule the said ban in public interest.

**143. Officers to be Public Servants.** - (1) All Officers and persons empowered to exercise any powers or to perform any functions under the Act or these rules shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 ( Act 45 of 1860).

(2) No suit shall lie in any Civil Court against the State Government or any Mining Officer for damages for any act done in good faith or ordered to be done in pursuance of the Act or these rules or of any other law for the time being in force relating to the Mining Revenue.

(3) No Civil Court shall try any suit against the State Government in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of these rules, and except with the previous sanction of the State Government, no Magistrate shall take cognizance of any charge made against any Mining Officer under these rules or made against any other person under these rules.

**144. Orders to remain in Force.** - (1) Every Order, Notification, Rule or Regulation which was made under the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 (as amended from time to time), the Bihar

Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003, the Sand Policy, 2013 or by the Mines Commissioner, Collector, the Board Of Revenue or any other Mining Officer appointed under those Rules relating to the matter of Mining and which was in force immediately before the expiration thereof shall, in so far as such order or notification or rule or regulation is not inconsistent with the provisions of the Act and these rules, be deemed to continue in force and to have been made under the Act and these rules.

**145. Repeal and Savings.** - (1) The Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 (as amended from time to time), the Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003 and the Sand Policy, 2013 are hereby *repealed*.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules and Policy shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Act and these rules.

(3) All references in any provisions of the rules so repealed shall be construed as references to the corresponding provisions of these rules.

(4) All proceedings (including proceedings by way of investigations) pending before any Officer, Authority or Court, immediately before the commencement of these rules shall, on such commencement, be deemed to be proceedings pending before it as per these rules and shall continue to be dealt with accordingly.

**146. Power to remove difficulty.** - (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.

**147. Laying of Rules.** - (1) These rules, as soon as they are promulgated, shall be laid before each house of the State Legislature.

(2) Every notification issued under these rules shall, as soon as it is issued, be laid before each house of the State Legislature.

By Order of the Governor of Bihar,

SUSHIL KUMAR,

*Under Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 926-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>